EDU TERIA

E - D.N.A

Daily Newspaper Analysis

Prelims | Mains | Essay

By- Nikhil Ranjan

Useful For Prelims

Date: 17 December 2025

वर्ष 2014 में निर्मित हुआ था यह संग्रहालय | **गर्मजोशी** | प्रागैतिहासिक काल से अब तक की क्षेत्र की सभ्यतागत यात्रा को दर्शाता है

स्वयं वाहन चलाकर प्रधानमंत्री मोदी को संग्रहालय लेकर गए जार्डन के युवराज

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 16 दिसंबर।

भारत और जार्डन के संबंधों में गर्मजोशी को दर्शाते हुए अरब देश के युवराज अल हुसैन बिन अब्दुल्ला द्वितीय मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वयं वाहन चलाकर जार्डन संग्रहालय लेकर गए। युवराज पैगंबर मोहम्मद की 42वीं पीढ़ी के सीधे वंशज हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी साझा की।

सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मोदी ने कहा कि वह संग्रहालय में जार्डन के इतिहास और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को दिखाने के लिए अल-हुसैन के प्रति 'आभारी' हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने युवराज के साथ 'विस्तृत बातचीत' की है तथा 'जार्डन की प्रगति के प्रति उनका जुनून स्पष्ट रूप से नजर आया।

युवराज अल हुसैन बिन अब्दुल्ला द्वितीय मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वयं वाहन चलाकर जार्डन संग्रहालय लेकर जाते हुए।

मोदी ने कहा कि युवा विकास, खेल, अंतरिक्ष, नवाचार और दिव्यांगजनों के कल्याण को बढ़ावा देने जैसे क्षेत्रों में उनका योगदान वास्तव में उल्लेखनीय है। उन्होंने अल-हुसैन को जार्डन के विकास पथ को मजबूत करने के उनके प्रयासों में सफलता की शुभकामनाएं दीं। मोदी जार्डन के शाह अब्दुल्ला द्वितीय के निमंत्रण पर दो दिवसीय यात्रा पर सोमवार को जार्डन की राजधानी अम्मान पहुंचे थे। जार्डन प्रधानमंत्री की तीन देशों की चार दिवसीय यात्रा का पहला पड़ाव है।

इस यात्रा के दौरान वह इथियोपिया और ओमान भी जाएंगे। अम्मान के रस अल-ऐन जिले में स्थित जार्डन संग्रहालय देश का सबसे बड़ा संग्रहालय है। इसमें जार्डन की कुछ सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक और ऐतिहासिक धरोहरों का प्रदर्शन किया गया है।

वर्ष 2014 में निर्मित यह संग्रहालय प्रागैतिहासिक काल से लेकर वर्तमान समय तक क्षेत्र की सभ्यतागत यात्रा को दर्शाता है। संग्रहालय में 15 लाख वर्ष पुरानी जानवरों की हड्डियां और चूना प्लास्टर से बनीं 9,000 वर्ष पुरानी ऐन गजल की मूर्तियां हैं, जिन्हें दुनिया की सबसे प्राचीन मूर्तियों में से एक माना जाता है।

Jansatta Page No-1

भारत और जार्डन में पांच अहम समझौते, पांच साल में कारोबार होगा दोगुना

पीएम मोदी और किंग अब्दुल्ला द्वितीय के बीच वार्ता में सामरिक, ऊर्जा व कारोबारी संबंधों के सहयोग पर रहा जोर

दोनों देशों के बीच स्वच्छ ऊर्जा, जल प्रबंधन, संस्कृति और डिजिटल नवाचार जैसे क्षेत्रों में समझौते हुए

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

पश्चिम एशियाई देशों के साथ भारत के संबंधों को नई धार देने के मकसद से जार्डन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दोनों देशों के बीच सामरिक, ऊर्जा व कारोबारी संबंधों को नई ऊंचाई देने की नींव रख दी है। एशिया, अफ्रीका और यूरोप के चौराहे पर स्थित जार्डन क्षेत्रीय स्थिरता का प्रतीक है और साथ ही आतंकवाद व उग्रवाद के खिलाफ मजबूत आवाज उठाता है। यह देश भारत के लिए उर्वरक आपूर्ति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 37 वर्षों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यह पूर्ण द्विपक्षीय दौरा था जहां पीएम मोदी और जार्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय के बीच उच्च स्तरीय वार्ता में आतंकवाद के खिलाफ सहयोग, गाजा संकट, क्षेत्रीय शांति और आर्थिक साझेदारी पर गहन चर्चा हुई। मोदी ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय कारोबार को अगले पांच वर्षों में दोगुना करके पांच अरब डालर करने का लक्ष्य भी रखा है।

मोदी और किंग अब्दुल्ला द्वितीय के बीच दो स्तरों पर बातचीत हुई। वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच पांच महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, जो स्वच्छ ऊर्जा, जल प्रबंधन, संस्कृति और डिजिटल नवाचार जैसे क्षेत्रों से संबंधित हैं। एक समझौता नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग पर है। बाद में भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि दोनों नेताओं के बीच परमाणु ऊर्जा सहयोग स्थापित करने पर भी बात हुई है। एक समझौता जार्डन की पेट्रा और भारत की एलोरा गुफाओं के बीच आपसी समझबूझ बढ़ाने को लेकर है। बताते चलें कि पेट्रा की सबसे प्रसिद्ध पर्यटक केंद्रों में गिनती होती है।

दोनों नेताओं ने संयुक्त बयान में द्विपक्षीय व्यापार को अगले पांच वर्षों में पांच अरब डालर तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया। वर्तमान में भारत जार्डन का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। वर्ष 2024 में द्विपक्षीय व्यापार 2.8 अरब डालर रहा था। बयान में व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा, उर्वरक, कृषि, आइटी, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा और पर्यटन में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई गई।

आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ साझा रुख पर जोर देते हुए क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए सहयोग की प्रतिबद्धता दोहराई गई। पीएम मोदी और किंग अब्दुल्ला ने संयुक्त रूप से उद्योगपतियों को भी संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा- 'भारत और जार्डन के संबंध ऐतिहासिक, विश्वास और भविष्य की आर्थिक संभावनाओं का अनोखा मिश्रण हैं। जार्डन की भौगोलिक स्थिति और भारत की स्किल्स व टैलेंट जब जुड़ेंगे तो दोनों देशों के युवाओं के लिए नई संभावनाएं खुलेंगी।' पीएम ने पुराने व्यापारिक मार्गों, जैसे गुजरात से पेट्रा होते हुए यूरोप को पुनर्जीवित करने की बात की और जार्डन को क्षेत्रीय हब बनाने पर जोर दिया। उन्होंने जार्डन की कंपनियों को आठ प्रतिशत से भी ज्यादा तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने जार्डन को भारतीय कृषि प्रौद्योगिकी प्रदान करने की भी पेशकश की। किंग अब्दुल्ला ने पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की उल्लेखनीय विकास की सराहना की और जार्डन की रणनीतिक स्थिति का उपयोग कर संयुक्त निवेश की वकालत की।

अम्मान में जार्डन के क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला द्वितीय से चर्चा करते प्रधानमंत्री मोदी। एएनआइ

इथियोपिया पहुंचे मोदी, दोनों देश और प्रगाढ़ करेंगे संबंध

पीएम मोदी मंगलवार को अपने तीन राष्ट्रों के दौरे के दूसरे चरण में इथियोपिया पहुंचे, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करना है। इथियोपिया के पीएम उन्हें खुद एयरपोर्ट लेने पहुंचे। उन्होंने होटल जाते वक्त मोदी को रास्ते में विज्ञान संग्रहालय और मित्रता पार्क भी दिखाया, हालांकि से तय यात्रा कार्यक्रम में नहीं था। इस दौरान पीएम अली ने अनौपचारिक बातचीत में अपने भारतीय समकक्ष को इथियोपियाई काफी की विभिन्न किस्मों के बारे में जानकारी दी। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि भारत-इथियोपिया के प्राचीन संबंधों का जश्न मनाते हुए पीएम मोदी इथोपिया पहुंचे। वहां मोदी का ग्रीन कारपेट स्वागत किया गया। इथियोपिया गभारत का एक प्रमुख साझेदार और एक ब्रिक्स सदस्य है। मोदी भारत-इथियोपिया द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। इथियोपिया के बाद मोदी अंतिम चरण में ओमान की यात्रा पर जाएंगे।

जार्डन में क्राउन प्रिंस तो इथियोपिया में पीएम अली ने मोदी की कार की ड्राइव

तीन देशों की यात्रा पर गए पीएम नरेन्द्र मोदी का जार्डन और इथियोपिया में जिस तरह से व्यक्तिगत स्वागत किया गया है वैसी मिसाल अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमेसी में बहुत ही कम देखने को मिलती है। जार्डन में क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला द्वितीय खुद गाड़ी चलाकर पीएम मोदी को जार्डन म्यूजियम ले गए और उसके बाद वहां जब कार्यक्रम समाप्त हो गया तो फिर एयरपोर्ट तक गाड़ी चला कर ले गए व मोदी को विदाई दी। यह दुर्लभ नजारा भारत-जार्डन मित्रता की गर्मजोशी का प्रतीक बना। जार्डन से इथियोपिया पहुंचते ही वहां एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री अबीय अहमद अली खुद मौजूद थे। नोबल पुरस्कार विजेता पीएम अली ने यहां खुद ही पीएम मोदी की गाड़ी को ड्राइव किया और उन्हें होटल ले जाकर छोड़ा।

अम्मान में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को खुद कार चलाकर जार्डन संग्रहालय लेकर पहुंचे क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला द्वितीय। एएनआइ

अदीस अबाबा हवाईअड्डे से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को कार चलाकर होटल छोड़ने जाते उनके इथियोपियाई समकक्ष अबीय अहमद अली। प्रेट्र

जयशंकर बोले, आतंकवाद पर भारत-इजरायल की 'जीरो टालरेंस' की नीति

यरुशलम, प्रेट्र: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सिडनी के बोंडी समुद्र तट पर रविवार को यहूदियों के त्योहार हनुक्का के जश्न के दौरान हुए आतंकी हमले पर गहरा दुख जताया और कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत और इजरायल की 'जीरो टालरेंस' की नीति है। गौरतलब है कि इस हमले में 15 लोग मारे गए और 40 घायल हो गए थे। एक हमलावर को मौके पर ही मार गिराया गया था, जबकि दूसरे को गिरफ्तार कर लिया गया। जयशंकर दो दिन के इजरायल दौरे पर मंगलवार को तेल अवीव पहुंचे और अपने इजरायली समकक्ष गिडिओन मोशे सा'र के साथ मीडिया से बातचीत की। जयशंकर ने कहा कि हनुक्का जश्न के दौरान आस्ट्रेलिया के बोंडी तट पर आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है। मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि हम इस घटना की कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ भारत को दिए समर्थन के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि दौरे पर वह दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा करेंगे, जो बीते एक दशक में महत्वपूर्ण तरीके से विकसित हुई है। जयशंकर ने कहा कि भारत और इजरायल एक दूसरे के साझेदार हैं और हमें इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने गाजा शांति योजना के लिए भारत के समर्थन को भी दोहराया और उम्मीद जताई कि इससे एक स्थायी और टिकाऊ समाधान निकलेगा।

Dainik Jagaran Page No-11

केंद्र ने न्यायालय से कहा

हर राज्य व केंद्र-शासित प्रदेश में एनआइए की समर्पित अदालत होगी

नई दिल्ली, 16 दिसंबर (भाषा)।

केंद्र सरकार ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि उसने आतंकवाद से जुड़े मामलों में त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए हर राज्य और केंद्र-शासित प्रदेश में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआइए) की एक समर्पित अदालत स्थापित करने का फैसला लिया है।

केंद्र ने शीर्ष अदालत को यह भी बताया कि उन राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों में एक से अधिक विशेष एनआइए अदालत स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, जहां आतंकवाद विरोधी कानून के तहत 10 से अधिक मामले विचाराधीन हैं। वहीं, दिल्ली सरकार ने प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जायमाल्या बागची की पीठ को बताया कि संगठित अपराध और आतंकवाद से जुड़े मामलों से निपटने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में 16 विशेष अदालतें स्थापित की जा रही हैं। पीठ ने केंद्र और दिल्ली सरकार से विभिन्न कानून प्रवर्तन एजंसियों के बीच क्षेत्राधिकार संबंधी किसी भी संघर्ष से बचने की खातिर पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के लिए महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) जैसा कड़ा संगठित अपराध-निरोधक कानून लागू करने की संभावनाएं तलाशने को कहा।

Jansatta Page No-12

बीमा क्षेत्र में 100 फीसद विदेशी निवेश के प्रावधान वाला विधेयक लोकसभा में पारित

नई दिल्ली, 16 दिसंबर (भाषा)।

लोकसभा ने बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआइ) को 100 फीसद तक बढ़ाने के प्रावधान वाले विधेयक को मंगलवार को मंजूरी दे दी। विधेयक पर चर्चा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जवाब के बाद सदन ने विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को खारिज करते हुए 'सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानूनों में संशोधन) विधेयक, 2025' को ध्वनि मत से स्वीकृति दे दी।

इससे पहले, विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए सीतारमण ने कहा कि बीमा विधेयक में अब तक 12 बार संशोधन हो चुका है तथा संशोधन भी कई तरह के होते हैं और ये देश की तरक्की एवं बीमा क्षेत्र की जरूरतों को प्रदर्शित करते हैं। उन्होंने कहा कि इस विधेयक में आम लोगों और किसानों की सुरक्षा के उपाय किए गए हैं। सीतारमण ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों की सुरक्षा के पुख्ता प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तीन बीमा कंपनियों की बेहतरी के लिए 17 हजार करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए और इस तरह के कदम से इनकी स्थिति में काफी सुधार हुआ है। सीतारमण ने कुछ विपक्षी सदस्यों के इन आरोपों को खारिज कर दिया कि प्रीमियम की राशि विदेशी कंपनियों के पास जाएगी।

बीमा विधेयक का लक्ष्य दायरा और पारदर्शिता बढ़ाना है : सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआइ) को 100 फीसद तक बढ़ाने वाले विधेयक का लक्ष्य दायरे को व्यापक करना है और सरकार नियामक को और सुदृढ़ करना चाहती है। सीतारमण ने 'सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानूनों में संशोधन) विधेयक, 2025' को लोकसभा में चर्चा और पारित के लिए रखते हुए कहा कि बीमा रकम की जरूरत को ध्यान में रखते हुए एफडीआइ को बढ़ाया जा रहा है और अनुपालन संबंधी कई नियमों को आसान किया गया है।

Jansatta Page No-12

71 पुराने कानूनों को खत्म करने वाला विधेयक लोस में पास

नई दिल्ली, 16 दिसंबर (भाषा)।

अप्रचलित और पुराने हो चुके 71 कानूनों को समाप्त करने या संशोधित करने के प्रावधान वाले 'निरसन और संशोधन विधेयक, 2025' को लोकसभा ने मंगलवार को मंजूरी दे दी। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस विधेयक को लेकर कुछ विपक्षी सदस्यों की आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा, 'यह विधेयक जल्दबाजी में नहीं, सोच-विचार कर-के लाया गया है और विकसित भारत की दिशा में बढ़ता कदम है।'

उन्होंने कहा कि 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद लगातार कानून बनाए जा रहे हैं, अनावश्यक कानूनों को निरस्त किया जा रहा है तथा कुछ कानूनों में आवश्यकतानुसार संशोधन किया जा रहा है।

मेघवाल ने कहा कि उक्त विधेयक गुलामी के अंशों से मुक्ति पाने, विकसित भारत, विरासत पर गर्व करने, एकजुट रहने और कर्तव्य भाव को बढ़ाने के प्रधानमंत्री मोदी के 'पंच प्रण' के तहत लाया गया है। उन्होंने कहा, 'हमारे शासनकाल में अगर हमें लगेगा कि हमें लोगों को व्यापार सुगमता के लिए प्रोत्साहित करना है, लोगों को समान अधिकार देने हैं, नागरिकों को सुविधा देनी है तो निश्चित रूप से मोदी सरकार इस दिशा में आगे बढ़ेगी।' मेघवाल के जवाब के बाद सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी प्रदान की।

उन्होंने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से छह अधिनियमों को निरस्त किया जाएगा और 65 में संशोधन किया जाएगा।

Jansatta Page No-12

इससे पहले अक्तूबर 2025 में 5.2 फीसद थी | सुधार | ग्रामीण बेरोजगारी दर घटकर नए निचले स्तर 3.9 फीसद पर आई

बेरोजगारी दर नवंबर में घटकर सात माह के निचले स्तर 4.7 फीसद पर

नई दिल्ली, 16 दिसंबर (भाषा)।

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के बीच बेरोजगारी दर नवंबर 2025 में घटकर 4.7 फीसद हो गई, जो अप्रैल 2025 के बाद का सबसे निचला स्तर है। यह इससे पहले अक्तूबर 2025 में 5.2 फीसद थी।

मंत्रालय ने कहा कि नवंबर 2025 में ग्रामीण बेरोजगारी दर घटकर नए निचले स्तर 3.9 फीसद पर आ गई, जबकि शहरी बेरोजगारी दर घटकर 6.5 फीसद रह गई, जो अप्रैल 2025 में दर्ज किए गए इसके पिछले न्यूनतम स्तर के बराबर है। अप्रैल 2025 में बेरोजगारी दर 5.1 फीसद थी।

बयान के अनुसार कुल मिलाकर रुझान श्रम बाजार की स्थितियों के मजबूत होने का संकेत देते हैं, जिन्हें ग्रामीण रोजगार में बढ़ोतरी, महिला भागीदारी में वृद्धि और शहरी श्रम मांग में क्रमिक सुधार का समर्थन मिला है।

मंत्रालय ने कहा कि नवंबर 2025 में ग्रामीण बेरोजगारी दर घटकर नए निचले स्तर 3.9 फीसद पर आ गई, जबकि शहरी बेरोजगारी दर घटकर 6.5 फीसद रह गई, जो अप्रैल 2025 में दर्ज किए गए इसके पिछले न्यूनतम स्तर के बराबर है। अप्रैल 2025 में बेरोजगारी दर 5.1 फीसद थी। बयान के अनुसार कुल मिलाकर रुझान श्रम बाजार की स्थितियों के मजबूत होने का संकेत देते हैं, जिन्हें ग्रामीण रोजगार में बढ़ोतरी, महिला भागीदारी में वृद्धि और शहरी श्रम मांग में क्रमिक सुधार का समर्थन मिला है। नवंबर 2025 में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुषों और महिलाओं, दोनों के लिए बेरोजगारी दर में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई।

नवंबर 2025 में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुषों और महिलाओं, दोनों के लिए बेरोजगारी दर में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई। महिलाओं के बीच बेरोजगारी दर नवंबर 2025 में घटकर 4.8 फीसद रह गई, जो अक्तूबर 2025 में 5.4 फीसद थी। यह गिरावट ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में महिला बेरोजगारी दर में कमी के कारण आई। ग्रामीण क्षेत्रों में यह 4.0 फीसद से घटकर 3.4 फीसद और शहरी क्षेत्रों में 9.7 फीसद से घटकर 9.3 फीसद हो गई। इसके अलावा, कुल पुरुष बेरोजगारी दर नवंबर 2025 में घटकर 4.6 फीसद रह गई, जो अक्तूबर 2025 में 5.1 फीसद थी। क्षेत्रवार आंकड़ों के अनुसार नवंबर 2025 में ग्रामीण और शहरी पुरुष बेरोजगारी दर क्रमशः 4.1 फीसद और 5.6 फीसद रही, जबकि इससे पिछले महीने यह क्रमशः 4.6 फीसद और 6.1 फीसद थी।

बयान में कहा गया कि अप्रैल से नवंबर 2025 के दौरान पुरुषों, महिलाओं और कुल व्यक्तियों के बीच बेरोजगारी दर में स्थिर और व्यापक आधार पर गिरावट दर्ज की गई। बयान के मुताबिक 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए श्रमिक-जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) में नवंबर 2025 में सुधार हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में डब्ल्यूपीआर अप्रैल 2025 के 55.4 फीसद से बढ़कर नवंबर 2025 में 56.3 फीसद हो गया, जबकि इसी अवधि में कुल डब्ल्यूपीआर 52.8 फीसद से बढ़कर 53.2 फीसद हो गया।

Jansatta Page No-12

पहली बार इथियोपिया पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी

संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर जताई सहमति

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 16 दिसंबर।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इथियोपिया के प्रधानमंत्री डाक्टर अबी अहमद अली के साथ द्विपक्षीय वार्ता की तथा इस दौरान भारत और इथियोपिया ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी तीन देशों की चार दिवसीय यात्रा के दूसरे चरण के तहत मंगलवार को इथियोपिया पहुंचे।

इथियोपिया के प्रधानमंत्री डाक्टर अबी अहमद अली ने अदीस अबाबा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मोदी का स्वागत किया। वह मोदी को अपनी गाड़ी में बैठाकर होटल तक भी ले गए। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान कहा कि हम भारत और इथियोपिया के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जा रहे हैं। यह कदम हमारे संबंधों को नई ऊर्जा, नई गति और नई गहराई प्रदान करेगा। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में सहयोग देने के लिए प्रधानमंत्री अली को धन्यवाद दिया। मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ इस संघर्ष में मित्र देशों का समर्थन अत्यंत महत्वपूर्ण है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज हमें अर्थव्यवस्था, नवाचार, प्रौद्योगिकी, रक्षा, स्वास्थ्य और बहुपक्षीय सहयोग जैसे हमारे सहयोग के प्रमुख पहलुओं पर विचार-विमर्श करने का अवसर मिला। मुझे खुशी है कि आज हमने भारत में इथियोपिया के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति को दोगुना करने का निर्णय लिया है। मोदी ने कहा कि भारत और इथियोपिया के बीच हजारों वर्षों से संपर्क, संवाद और आदान-प्रदान होता रहा है।

इथियोपिया के प्रधानमंत्री डाक्टर अबी अहमद अली के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।

इथियोपिया ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च सम्मान से नवाजा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंगलवार को उनके इथियोपियाई समकक्ष अबी अहमद अली ने इथियोपिया के सर्वोच्च सम्मान 'द ग्रेट आनर निशां आफ इथियोपिया' से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान मंगलवार को अदीस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में आयोजित एक विशेष समारोह में प्रदान किया गया। विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली में जारी एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को भारत-इथियोपिया साझेदारी को मजबूत करने में उनके असाधारण योगदान और वैश्विक राजनेता के रूप में उनके दूरदर्शी नेतृत्व के लिए यह सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी यह सम्मान प्राप्त करने वाले पहले वैश्विक राष्ट्राध्यक्ष/सरकार प्रमुख हैं।

प्रमुख क्षेत्रों में भारत और जार्डन के बीच साझेदारी हुई मजबूत : मोदी

नई दिल्ली, 16 दिसंबर (ब्यूरो)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि शाह अब्दुल्ला द्वितीय के साथ उनकी वार्ता ने नवीकरणीय ऊर्जा, जल प्रबंधन, डिजिटल परिवर्तन, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और विरासत सहयोग समेत प्रमुख क्षेत्रों में भारत-जार्डन साझेदारी को मजबूत किया है।

दो दिवसीय यात्रा के अंत में मोदी ने कहा कि मेरी जार्डन यात्रा बेहद फलदायी रही है। उन्होंने शाह अब्दुल्ला द्वितीय और जार्डन के लोगों को उनकी 'असाधारण' मित्रता के लिए धन्यवाद दिया।

मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि हमारी चर्चाओं ने नवीकरणीय ऊर्जा, जल प्रबंधन, डिजिटल परिवर्तन, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और विरासत सहयोग जैसे प्रमुख क्षेत्रों में भारत-जार्डन साझेदारी को मजबूत किया है। हमने मिलकर जो परिणाम हासिल किए हैं, वे हमारे नागरिकों के लिए प्रगति और समृद्धि के नए रास्ते खोलेंगे। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता से पहले सोमवार को मोदी ने हुसैनीया महल में शाह अब्दुल्ला द्वितीय के साथ आमने-सामने बैठक की। मंगलवार को जारी एक संयुक्त बयान के अनुसार, दोनों नेताओं ने अपने देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंधों की सराहना की, जिसकी पहचान आपसी विश्वास, सौहार्द और सद्भावना है। इसमें कहा गया है कि दोनों ने भारत-जार्डन के बहुआयामी संबंधों का सकारात्मक मूल्यांकन किया है, जो राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा, संस्कृति और शिक्षा सहित सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए हैं।

पांच वर्ष में व्यापार को दोगुना कर पांच अरब डालर करने का प्रस्ताव

नई दिल्ली, 16 दिसंबर (ब्यूरो)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत-जार्डन द्विपक्षीय व्यापार को अगले पांच वर्ष में दोगुना करके पांच अरब अमेरिकी डालर तक पहुंचाने का प्रस्ताव रखा। साथ ही उन्होंने जार्डन की कंपनियों को देश की उच्च आर्थिक वृद्धि का लाभ उठाने और अच्छा मुनाफा कमाने के लिए आमंत्रित किया। मोदी सोमवार को जार्डन की राजधानी अम्मान पहुंचे थे। प्रधानमंत्री मोदी और किंग अब्दुल्ला द्वितीय ने भारत-जार्डन व्यापार मंच को मंगलवार को संबोधित किया। इस सम्मेलन में युवराज हुसैन और जार्डन के व्यापार एवं उद्योग मंत्री तथा निवेश मंत्री भी उपस्थित रहे।

शांति प्रस्ताव को कुछ दिनों में दिया जाएगा अंतिम रूप : जेलेंस्की

कीव, 16 दिसंबर (एपी)।

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि रूस के साथ पिछले चार साल से जारी युद्ध को समाप्त करने के लिए अगले कुछ दिनों में अमेरिकी अधिकारियों के साथ बातचीत के बाद शांति समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि इसके बाद अमेरिकी दूत अगले सप्ताहांत अमेरिका में संभावित बैठकों से पहले समझौते के मसौदे को रूस के समक्ष प्रस्तुत करेंगे जेलेंस्की ने सोमवार देर रात संवाददाताओं से कहा कि बर्लिन में दिन में अमेरिका के साथ चर्चा की गई शांति योजना का मसविदा बहुत ही व्यावहारिक है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने हालांकि आगाह किया कि रूस के कब्जे में उसके क्षेत्र सहित कुछ मुद्दे हैं, जो अब भी अनसुलझे हैं। अमेरिका के नेतृत्व में की जा रही शांति की कोशिशें आगे बढ़ती प्रतीत हो रही हैं। लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अमेरिका, यूक्रेन और पश्चिमी यूरोप के अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए कुछ प्रस्तावों पर आपत्ति जता सकते हैं, जिनमें यूक्रेन के लिए युद्धोत्तर सुरक्षा गारंटी भी शामिल है। अमेरिकी अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि उनके द्वारा तैयार की गई शांति योजना के लगभग 90 प्रतिशत बिंदुओं पर यूक्रेन और यूरोप में सहमति है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि हम शांति समझौते के पहले से कहीं अधिक करीब हैं। हालांकि, अब भी कई मुद्दों पर गतिरोध बना हुआ है। जेलेंस्की ने दोहराया कि यूक्रेन, देश के आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण डोनबास क्षेत्र के किसी भी हिस्से पर रूस के नियंत्रण को मान्यता नहीं देगा।

अगले वित्त वर्ष में भी 7.5 प्रतिशत रहेगी भारत की आर्थिक वृद्धि दर

- एक्सिस बैंक ने इकोनमी आउटलुक 2026 में जताया अनुमान
- सरकारी खर्च पर दबाव कम होने से इकोनमी में तेज वृद्धि होने की संभावना जताई

मुंबई, आइएएनएस: भारत की आर्थिक वृद्धि आने वाले वर्षों में तेज होगी और मजबूत बनी रहेगी। इसके साथ ही अगले वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक वृद्धि 7.5 प्रतिशत रह सकती है। एक्सिस बैंक के इकोनमी आउटलुट 2026 में यह बात कही गई है।

एक्सिस बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री और एक्सिस कैपिटल के वैश्विक शोध प्रमुख नीलकंठ मिश्रा का कहना है कि यह वृद्धि संरचनात्मक और नियामक सुधारों, कम उधारी लागत, तेज पूंजी निर्माण और नीतिगत ढील से मिलने वाले चक्रीय समर्थन के कारण होगी। मिश्रा और बैंक की आर्थिक शोध टीम का मानना है कि इकोनमी में सुस्ती को देखते हुए महंगाई के दबाव के बिना भी रुझान से बेहतर वृद्धि बनी रह सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकारी खर्च पर दबाव कम होने और अनुकूल मौद्रिक नीतियों के चलते अर्थव्यवस्था में 7.5 प्रतिशत से ज्यादा की तेज वृद्धि हो सकती है। साथ ही, सरल नियमों और सुधारों से आने वाले समय में विकास को और मजबूती मिलेगी। बेहतर वित्तीय स्थिति, पूंजी की कम लागत और उच्च क्षमता उपयोग (जिससे नए पूंजीगत निवेश की जरूरत बनेगी) के कारण अगले वित्त वर्ष में पूंजीगत व्यय में बढ़ोतरी होने की संभावना है। वित्त वर्ष 2026-27 में औसत महंगाई करीब चार प्रतिशत रहने की संभावना है। पिछले 18 महीनों से महंगाई लगभग तीन प्रतिशत पर स्थिर है।

Dainik Jagaran Page No-10

इंट्रा-डे में पहली बार 91 के पार पहुंचा रुपया

दिनभर के कारोबार के बाद डालर के मुकाबले 15 पैसे गिरकर 90.93 के स्तर पर बंद हुई भारतीय मुद्रा

मुंबई, प्रेट्र: अमेरिकी डालर के मुकाबले भारतीय रुपये में गिरावट का दौर जारी है। विदेशी फंडों की लगातार निकासी, भारत-अमेरिका व्यापार समझौते में कोई प्रगति नहीं होने और अमेरिकी डालर की लगातार खरीदारी के चलते मंगलवार को भारतीय मुद्रा इंट्रा-डे में पहली बार 91 के स्तर को पार करके 91.14 के सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंचा। हालांकि, अंत में यह थोड़े सुधार के बाद 15 पैसे गिरकर 90.93 के नए निचले स्तर पर बंद हुई। इस बीच सरकार ने घरेलू मुद्रा की गिरती कीमत का कारण बढ़ता व्यापार घाटा और भारत-अमेरिका व्यापार समझौते से जुड़े घटनाक्रमों को बताया है।

विदेशी मुद्रा व्यापारियों के अनुसार, कमजोर डालर और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट भी स्थानीय मुद्रा की गिरावट को रोकने में असफल रही। पिछले 10 कारोबारी सत्रों में रुपये 90 से 91 के स्तर तक गिर चुका है। पिछले पांच सत्रों में ही यह एक प्रतिशत गिरा है। विदेशी मुद्रा व्यापारियों के अनुसार, इस महीने रुपया 92 प्रति डालर के स्तर को भी पार कर सकता है। सोमवार को रुपया 29 पैसे गिरकर 90.78 प्रति डालर पर बंद हुआ था।

फिनरेक्स ट्रेजरी एडवाइजर्स के कार्यकारी निदेशक अनिल कुमार भंसाली के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के नए व्यापार प्रस्तावों पर सहमति नहीं दी है। इसका भारतीय मुद्रा पर प्रतिकूल असर दिखा है।

राज्यसभा में उठा रुपये के गिरने का मुद्दा : रुपये में गिरावट का मुद्दा मंगलवार को राज्यसभा में भी उठाया गया। इस पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में रुपये की गिरावट व्यापार खाते में वृद्धि और अमेरिका के साथ भारत के व्यापार समझौते को लेकर चल रहे घटनाक्रमों के कारण हुई है। साथ की पूंजी खाते से भी अपेक्षाकृत कमजोर मदद मिली है। उन्होंने कहा कि रुपये में गिरावट से निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ने की संभावना है जिसका इकोनमी पर सकारात्मक असर पड़ता है। दूसरी ओर, गिरावट से आयातित सामानों की कीमतें बढ़ सकती हैं। हालांकि, घरेलू कीमतों पर विनिमय दर में गिरावट का कुल असर इस बात पर निर्भर करता है कि वैश्विक कमोडिटी की कीमतों का घरेलू बाजार में कितना प्रभाव होता है। डाटा के हवाले से चौधरी ने कहा कि इस वर्ष में तीन दिसंबर तक रुपया 5.1 प्रतिशत गिर चुका है। डाटा के अनुसार, अमेरिकी डालर के मुकाबले 2015 में रुपया 4.5 प्रतिशत, 2016 में 2.6 प्रतिशत गिरा था, जबकि 2017 में 6.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी।

2018 से लगातार गिर रहा रुपया

केंद्रीय मंत्री की ओर से साझा किए गए डाटा के अनुसार, 2018 से रुपये में लगातार गिरावट आई है। डालर के मुकाबले 2018 में यह 8.5 प्रतिशत, 2019 में 2.3 प्रतिशत, 2020 में 2.3 प्रतिशत, 2021 में 1.7 प्रतिशत, 2022 में 10.2 प्रतिशत, 2023 में 0.6 प्रतिशत, और 2024 में 2.8 प्रतिशत गिरा था। उन्होंने कहा कि रुपया का मूल्य बाजार तय करता है। इसके लिए कोई खास लक्ष्य, स्तर या बैंड तय नहीं है। आरबीआइ विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार की नियमित निगरानी करता है। ज्यादा उतार-चढ़ाव पर दखल देता है।

- केंद्र सरकार ने राज्यसभा में रुपये में गिरावट के कई कारण बताए
- भारत-अमेरिका व्यापार समझौते से जुड़े घटनाक्रम है प्रमुख वजह

कमजोर वैश्विक संकेतों से 533 अंक टूटा सेंसेक्स

मुंबई, प्रेट्र : विदेशी फंडों की लगातार निकासी, रुपये में गिरावट और कमजोर वैश्विक संकेतों के चलते भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को गिरकर बंद हुए। बीएसई का मानक सूचकांक सेंसेक्स 533.50 अंक गिरकर 85 हजार के स्तर से नीचे गिरकर 84,679.86 पर बंद हुआ। दिनभर के कारोबार में इसमें 592.75 अंक तक की गिरावट रही। इसी तरह, एनएसई का निफ्टी 167.20 अंक गिरकर 25,860.10 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स में एक्सिस बैंक के शेयरों में सबसे ज्यादा 5.03 प्रतिशत की गिरावट रही। इसके अलावा एटरनल, एचसीएल टेक, बजाज फिनसर्व, टाटा स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट और बजाज फाइनेंस के शेयर भी गिरकर बंद हुए। दूसरी ओर टाइटन, भारती एयरटेल महिंद्रा एंड महिंद्रा और एशियन पेंट्स के शेयर बढ़कर बंद हुए।

Dainik Jagaran Page No-10

600 अरब डालर की संपत्ति वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने मस्क

नई दिल्ली, आइएएनएस: अमेरिका के दिग्गज कारोबारी और इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने एक और इतिहास रचा है। वे 600 अरब डालर या इससे ज्यादा की संपत्ति वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। फोर्ब्स के अनुसार, सोमवार को उनकी कुल संपत्ति करीब 677 अरब डालर हो गई थी। इसके साथ ही मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर बनने की राह में एक कदम और आगे बढ़ गए हैं।

मस्क की संपत्ति में यह उछाल मुख्य रूप से उनकी स्पेस कंपनी स्पेसएक्स की वजह से आया है। दरअसल, स्पेसएक्स अगले वर्ष 1.5 ट्रिलियन डालर के मूल्यांकन पर आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आइपीओ लाने की तैयारी कर रही है। हाल ही में कंपनी का मूल्यांकन 800 अरब डालर तक पहुंचा है। मस्क के पास स्पेसएक्स में करीब 42 प्रतिशत हिस्सेदारी है। कंपनी के मूल्यांकन में बढ़ोतरी से मस्क की संपत्ति में 168 अरब डालर की बढ़ोतरी हुई है। मस्क अक्टूबर में ही 500 अरब डालर की संपत्ति का आंकड़ा पार करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने थे।

एलन मस्क

- 677 अरब डालर हुई टेस्ला के सीईओ की कुल संपत्ति
- स्पेसएक्स का बाजार मूल्यांकन बढ़ने से संपत्ति में वृद्धि हुई

इसके अलावा, मस्क की इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला ने भी उनकी संपत्ति बढ़ाने में मदद की है। टेस्ला के शेयर इस साल अब तक 13 प्रतिशत बढ़ चुके हैं। भले ही कंपनी की बिक्री में गिरावट आई है। मस्क की टेस्ला में करीब 12 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

Dainik Jagaran Page No-10

2026 में चार से छह देशों के साथ हो सकते हैं व्यापार समझौते

राजीव कुमार ● जागरण

- नए साल में ईयू के साथ सबसे पहले व्यापार समझौता होने की संभावना ,ब्रिटेन के साथ हो चुके एफटीए पर मार्च या अप्रैल में अमल शुरू होगा
- अमेरिका के साथ नए साल में कभी भी पहले चरण का व्यापार समझौता, इन समझौतों से भारत को निर्यात के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा

नई दिल्ली: व्यापार के लिहाज से वर्ष 2026 मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) का वर्ष होगा। नए साल में सबसे पहले यूरोपीय यूनियन (ईयू) के साथ एफटीए हो सकता है और उसके बाद न्यूजीलैंड के साथ। मार्च या अप्रैल में ब्रिटेन के साथ हो चुके एफटीए पर अमल शुरू हो जाएगा। नए साल में पेरू व चिली के साथ भी व्यापार समझौते की संभावना है। पेरू के साथ व्यापार समझौते को लेकर नौ चरण तो चिली के साथ चार चरण की वार्ता पूरी की जा चुकी है। कनाडा के साथ एक बार फिर से व्यापार समझौते को लेकर हाल ही में बातचीत शुरू की गई है। अमेरिका के साथ भी द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर छह चरण की वार्ता पूरी हो चुकी है और नए साल में कभी भी पहले चरण का व्यापार समझौता हो सकता है।

वाणिज्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, आगामी जनवरी में वाणिज्य व उद्योग मंत्री ईयू के मुख्यालय ब्रसेल्स का दौरा करेंगे और बहुत उम्मीद है कि इस दौरान भारत व ईयू के बीच व्यापार समझौते को अंतिम रूप दे दिया जाए। गत 3-9 दिसंबर के बीच व्यापार समझौते पर वार्ता के लिए ईयू की टीम भारत में थी। 8-9 दिसंबर को ईयू और भारत के वाणिज्य मंत्री के बीच बैठक की गई जिसमें दोनों ओर की टीम को व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने को लेकर विभिन्न प्रकार के निर्देश दिए गए।

ईयू में फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, स्पेन जैसे विकसित देशों को मिलाकर दो दर्जन से अधिक देश शामिल हैं। ईयू के साथ व्यापार समझौता हो जाने पर आगामी वित्त वर्ष 2026-27 में भारतीय निर्यात नई ऊंचाई को छू सकता है।

चिली और पेरू के साथ एफटीए होने से दक्षिण अमेरिका में भारतीय व्यापार के लिए नए दरवाजे खुलेंगे। ऐसा नहीं है कि ईयू व अन्य देशों के साथ एफटीए होने से सिर्फ वस्तु निर्यात को ही फायदा होगा। सभी एफटीए में सेवा सेक्टर के साथ लोगों की आवाजाही को प्राथमिकता को भी शामिल किया जा रहा है। इसका फायदा यह होगा कि इन देशों में आइटी व अन्य सेवा क्षेत्र के निर्यात के साथ भारतीय श्रमिकों व प्रोफेशनल्स को भी वहां काम करने का मौका मिलेगा। इससे भी विदेशी मुद्रा अर्जित करने में मदद मिलेगी। विभिन्न देशों के साथ व्यापार समझौतों का एक फायदा यह भी होगा कि निर्यात के लिए भारत किसी देश पर निर्भर नहीं रहेगा और भारतीय निर्यात के लिए बाजार का विकल्प बढ़ता जाएगा।

ओमान के साथ 18 दिसंबर को सीपा

भारत और ओमान के बीच 18 दिसंबर को कंप्रेहेंसिव इकोनमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (सीपा) होने जा रहा है। पिछले दो साल से दोनों देशों के बीच सीपा को लेकर वार्ता चल रही थी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अभी तीन देश के दौरे पर हैं और आखिर में ओमान जाएंगे। ओमान गल्फ कोआपरेशन कंट्रीज (जीसीसी) का सदस्य है। इस कारण ओमान के साथ सीपा होने से जीसीसी के अन्य सदस्य देशों के साथ भी व्यापार बढ़ाने में मदद मिलेगी। ओमान व भारत के बीच अभी सालाना 10.6 अरब डालर का कारोबार होता है। इसमें भारत का निर्यात 4.1 अरब डालर का है। ओमान से भारत गैस, पेट्रोलियम पदार्थ जैसे आइटम का आयात करता है।

Dainik Jagaran Page No-10

मंथन

डा. अतुल अग्रवाल

भारतीय प्रबंधन संस्थान, सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

जल की मांग पूरी करने की चुनौती

जल संकट केवल प्राकृतिक संसाधन की कमी नहीं, बल्कि नीति, प्रौद्योगिकी और व्यवहार, तीनों स्तरों पर असंतुलन का परिणाम है

संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 के अनुसार, विश्व की लगभग 2.2 अरब आबादी को आज भी स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं है। भारत में स्थिति और भी चिंताजनक है, क्योंकि यहां विश्व की 18 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, जबकि देश के पास वैश्विक मीठे जल संसाधनों का केवल चार प्रतिशत हिस्सा है। नीति आयोग की कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार, भारत के 21 से अधिक प्रमुख शहर जैसे दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु और जयपुर अगले दशक में "डे जीरो" की स्थिति का सामना कर सकते हैं। अर्थात जब नल का जल पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। जल की मांग और आपूर्ति के बीच बढ़ता अंतर न केवल विकास की गति को रोक सकता है, बल्कि सामाजिक असमानता और संघर्षों को भी जन्म दे सकता है।

भारत में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता 1951 में जहां 5177 घनमीटर थी, वह 2021 में घटकर केवल 1486 घनमीटर रह गई है। केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के अनुसार यदि यही प्रवृत्ति जारी रही, तो 2050 तक यह आंकड़ा 1200 घनमीटर से भी नीचे चला जाएगा, जिसे जल-संकटग्रस्त राष्ट्र की श्रेणी माना जाता है। यह गिरावट प्राकृतिक नहीं, बल्कि हमारे जल उपयोग व्यवहार और प्रबंधन की विफलता का परिणाम है। देश के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में जल वितरण अवसंरचना अत्यंत कमजोर है। नेशनल इंस्टीट्यूट आफ अर्बन अफेयर्स (एनआइयूए) के 2022 के अध्ययन के अनुसार, शहरी जल आपूर्ति नेटवर्क से 35 से 40 प्रतिशत जल पाइपलाइन रिसाव के कारण नष्ट हो जाता है।

कृषि क्षेत्र में भारत के कुल जल उपयोग का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा खर्च होता है। फूड एंड एग्रीकल्चर आर्गनाइजेशन (एफएओ) के अनुसार, भारत में प्रति हेक्टेयर सिंचाई जल खपत वैश्विक औसत से लगभग दोगुनी है। इसके बावजूद कृषि उत्पादकता उतनी अधिक नहीं बढ़ पाई है, क्योंकि अधिकांश किसान "फ्लड इरिगेशन" जैसी पारंपरिक पद्धतियों का उपयोग करते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आइसीएआर) की एक रिपोर्ट 2023 के अनुसार, यदि माइक्रो-इरिगेशन (ड्रिप और सिंप्रंकलर) तकनीक का उपयोग देशभर में किया जाए, तो सिंचाई जल की खपत में 45 प्रतिशत तक की बचत संभव है। इसके अतिरिक्त, गन्ना और धान जैसी जल-प्रधान फसलें महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा जैसे सीमित जल वाले राज्यों में उगाई जा रही हैं। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के अनुसार, हरियाणा में 85 प्रतिशत और पंजाब में 75 प्रतिशत ब्लाक 'अतिदोहन क्षेत्र' घोषित हो चुके हैं, जहां भूजल स्तर प्रति वर्ष औसतन एक मीटर गिर रहा है।

घरेलू और शहरी जल उपयोग में भी भारी असंतुलन देखा जा सकता है। ब्यूरो आफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (बीआइएस) के अनुसार, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 135 लीटर जल उपयोग की अनुशंसा की गई है, जबकि दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में यह आंकड़ा 220 लीटर से अधिक है। इनमें से लगभग 30 प्रतिशत जल बाथरूम, वाहन धुलाई और फर्श सफाई जैसे गैर-आवश्यक कार्यों में व्यर्थ जाता है। यदि प्रत्येक घर में जल पुनः उपयोग प्रणाली और वर्षा जल संचयन की व्यवस्था लागू की जाए तो शहरी जल संकट को 25-30 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है।

नीति आयोग के अनुसार यदि भारत के प्रत्येक शहरी भवन में छत-आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली लागू की जाए, तो प्रति वर्ष लगभग 45 अरब घनमीटर जल संरक्षित किया जा सकता है, जो देश की कुल शहरी जल मांग का लगभग 30 प्रतिशत है।

जल का उपयोग जिम्मेदारी से करना सीखें लोग। फाइल

जल संकट केवल प्राकृतिक संसाधन की कमी नहीं, बल्कि नीति, प्रौद्योगिकी और व्यवहार, तीनों स्तरों पर असंतुलन का परिणाम है। हमें जल को पुनर्चक्रित करने, पुनः उपयोग करने और समान वितरण के लिए वैज्ञानिक रणनीतियां अपनानी होंगी। "वाटर फुटप्रिंट" की अवधारणा को नागरिक जीवन में उतारने की आवश्यकता है, ताकि हर व्यक्ति अपने जल उपयोग की जिम्मेदारी समझ सके। सरकार को "एक भवन, एक जल-योजना" नीति लागू करनी चाहिए, जिसमें वर्षा जल संचयन, ग्रे-वाटर रीसाइक्लिंग और जल आडिट अनिवार्य हों। राजस्थान के अलवर जैसे शहरों में जहां दो- तीन दिन में एक बार बीस मिनट के लिए ही जलापूर्ति होती है, वहां यह संकट चेतावनी नहीं, बल्कि आपातकाल बन चुका है। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जल केवल सरकार नहीं, बल्कि समाज की साझी संपत्ति है। योजनाएं और नीतियां जल नहीं बना सकतीं, केवल सामूहिक समझ और अनुशासित उपभोग ही जल को बचा सकता है। यदि आज हमने वैज्ञानिक और सामाजिक दृष्टि से जल प्रबंधन को प्राथमिकता नहीं दी, तो आने वाले दशकों में भारत का हर शहर "जल संकट मानचित्र" का हिस्सा बन जाएगा। जल संरक्षण केवल पर्यावरणीय मुद्दा नहीं, बल्कि मानव सभ्यता के अस्तित्व की वैज्ञानिक परीक्षा है।

Dainik Jagaran Page No-9

नृपेंद्र अभिषेक नृप
आर्थिक मामलों के जानकार

आजकल

आर्थिकी को गति देगी रेपो दर में कमी

हाल में रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कटौती की। हालांकि वैश्विक अनिश्चितताएं बरकरार हैं, फिर भी यह नीति दीर्घकालिक आर्थिक गति बनाए रखने और भारत को बाहरी झटकों से बचाने की रणनीति दर्शाती है। उम्मीद है कि इस कदम से उपभोक्ता खर्च बढ़ेगा, उद्योगों में सक्रियता आएगी, घरों पर वित्तीय बोझ कम होगा, निवेश को बल मिलेगा और आर्थिक आत्मविश्वास बढ़ेगा। असली परीक्षा यह होगी कि इसके लाभ सीधे आम लोगों तक पहुंचें और समावेशी विकास को प्रोत्साहन मिले

विकसित भारत के लिए दो अंकों में जीडीपी विकास आवश्यक। प्रतीकात्मक

भारत की मौद्रिक दिशा में एक अहम मोड़ सामने आया है। हाल में रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने नीतिगत ब्याज दर यानी रेपो दर को 25 आधार अंक घटाकर 5.25 प्रतिशत कर दिया। यह कदम उस समय उठाया गया है, जब भारत की अर्थव्यवस्था अपेक्षाकृत स्थिर स्थिति में दिखाई दे रही है। यानी महंगाई कम है, आर्थिक वृद्धि मजबूत है और उपभोक्ता मांग भी बेहतर बनी हुई है। कई विशेषज्ञों को उम्मीद थी कि सकारात्मक आर्थिक संकेतकों को देखते हुए रिजर्व बैंक दरों में बदलाव नहीं करेगा, लेकिन इसके उलट केंद्रीय बैंक ने एक भरोसेमंद और दूरदर्शी कदम उठाते हुए दरों में कटौती की है। वैश्विक अनिश्चितताओं, रुपये की गिरावट और भू-राजनीतिक तनाव के बीच यह निर्णय साहसिक भी है और समयोचित भी।

इस फैसले का महत्व समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि मौजूदा आर्थिक स्थिति क्या है, दरों में कटौती क्यों की गई, इससे किन क्षेत्रों को लाभ होगा और आगे किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? साल की पहली छमाही भारत के लिए बेहद अनुकूल रही है। महंगाई 2.2 प्रतिशत पर आ गई है, जो कई वर्षों का न्यूनतम स्तर है, जबकि जीडीपी वृद्धि आठ प्रतिशत तक पहुंच गई है। अर्थशास्त्र में इसे गोल्डीलाक्स पीरियड कहा जाता है, जहां वृद्धि तेज होती है और महंगाई नियंत्रित रहती है। वैश्विक उतार-चढ़ाव के बावजूद भारत की आंतरिक अर्थव्यवस्था ने मजबूत प्रदर्शन किया है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें, अंतरराष्ट्रीय तनाव और रुपये की कमजोरी जैसे दबावों के बीच भी घरेलू खपत, निवेश, निर्माण क्षेत्र और सेवाएं निरंतर अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। ऐसे माहौल में रेपो दर में कटौती यह संकेत देती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अतिरिक्त पूंजी को संभालने और आगे बढ़ने के लिए तैयार है।

दर कटौती की अनिवार्यता : रेपो दर, यानी वह ब्याज दर जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को कर्ज देता है, पूरे आर्थिक ढांचे में कर्ज की स्थिति तय करने में अहम भूमिका निभाती है। इस मानक दर में कमी का सीधा मतलब है कि उपभोक्ताओं और व्यवसायों को सस्ता कर्ज मिलेगा, जिससे खर्च, निवेश और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी। रेपो दर घटने से लोगों की क्रय शक्ति बढ़ती है। घर, वाहन, शिक्षा और व्यक्तिगत जरूरतों के लिए मिलने वाले कर्ज सस्ते हो जाते हैं, जिससे परिवार अधिक उधार लेने और खर्च करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। इसका सीधा असर रियल एस्टेट, आटोमोबाइल और रिटेल जैसे क्षेत्रों पर पड़ता है, जहां मांग में स्पष्ट सुधार देखने को मिलता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (एमएसएमई) क्षेत्र, जो भारतीय उद्योग की रीढ़ माना जाता है, कम ब्याज दरों से बड़ा लाभ उठाता है। सस्ता कर्ज इन्हें उत्पादन बढ़ाने, तकनीक में निवेश करने, अधिक लोगों को रोजगार देने और वित्तीय बाधाओं को पार करने में मदद करता है। बड़े उद्योग भी अपनी क्षमताओं का विस्तार करके निवेश बढ़ा सकते हैं, जिससे उत्पादन और विविधीकरण में बढ़ोतरी होती है। जब महंगाई नियंत्रण में हो और विकास मजबूत दिखाई दे, तब दर घटाना यह संदेश देता है कि रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था की बुनियादी मजबूती पर विश्वास रखता है। यह कोई तात्कालिक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि दीर्घकालिक आर्थिक गति बनाए रखने की सोची-समझी रणनीति है। महंगाई की दिशा को देखते हुए आरबीआइ आश्वस्त है कि कीमतें लक्ष्य सीमा में बनी रहेंगी।

अधिक बचत, अधिक स्थिरता : कई अर्थशास्त्रियों को उम्मीद थी कि रिजर्व बैंक दरों को यथावत रखेगा, क्योंकि अभी जीडीपी वृद्धि और महंगाई, दोनों ही अनुकूल स्तर पर हैं। ऐसे में स्थिरता बनाए रखना स्वाभाविक चुनाव माना जा रहा था, लेकिन रेपो दर में की गई यह हल्की कटौती पारंपरिक उम्मीदों से अलग है। यह संकेत देती है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत अपनी विकास गति बनाए रखना चाहता है, तेल की कीमतों और मुद्रा उतार-चढ़ाव के जोखिमों को संतुलित करना चाहता है, घरेलू निवेश को मजबूत करना चाहता है और लंबी अवधि की वृद्धि को स्थिर आधार देना चाहता है। साधारण भारतीय परिवार के लिए रेपो दर में कटौती सीधी आर्थिक राहत लेकर आती है। होम लोन, कार लोन और व्यक्तिगत कर्ज पर ईएमआइ कम होने से घरों के पास ज्यादा बचत योग्य आय रहती है। यह अतिरिक्त पैसा परिवार अपनी जरूरतों के अनुसार बचत, निवेश या खर्च में लगा सकते हैं। उपभोक्ता खर्च में बढ़ोतरी खासतौर पर खुदरा, पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था की गति को और मजबूत करेगी।

अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों के बीच राह बनाता भारत : भारत आज ऐसे वैश्विक माहौल में आर्थिक फैसले ले रहा है, जहां कई अंतरराष्ट्रीय चुनौतियां एक साथ सामने हैं। कोई भी केंद्रीय बैंक दुनिया से अलग होकर निर्णय नहीं ले सकता, क्योंकि वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां हर देश की मौद्रिक नीति को सीधे प्रभावित करती हैं। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें भारत के लिए बड़ी चिंता हैं, क्योंकि तेल हमारे आयात का प्रमुख हिस्सा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ने से परिवहन, उत्पादन और रोजमर्रा की वस्तुओं की लागत बढ़ती है, जिससे महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा होता है। इसके बावजूद रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर में कमी से साफ है कि उसे घरेलू मांग और आपूर्ति प्रबंधन पर भरोसा है। इसी तरह दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे भू-राजनीतिक तनाव वैश्विक व्यापार और सप्लाई चेन को बाधित करते हैं, जिनका असर उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर गहरा होता है। इस दौरान ब्याज दरों में कटौती का कदम भारत की आंतरिक अर्थव्यवस्था को बाहरी झटकों से बचाने की कोशिश है। इसके अलावा अमेरिका की टैरिफ नीतियों और फेडरल रिजर्व की ब्याज दरें वैश्विक पूंजी प्रवाह को प्रभावित करती हैं। अमेरिका में दरें बढ़ने पर पूंजी उभरते बाजारों से निकलती है, जिससे उनकी मुद्रा पर दबाव पड़ता है। रुपया पहले ही डालर के मुकाबले काफी कमजोर हुआ है, जिससे आयात महंगा हो गया है। इन सबके बावजूद रिजर्व बैंक ने अपने निर्णय से घरेलू बिक्री को प्राथमिकता देकर भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती पर भरोसा जताया है।

प्रमुख क्षेत्रों पर असर : रेपो दर में कमी का सबसे तेज और स्पष्ट असर रियल एस्टेट और आवास क्षेत्र पर पड़ता है, क्योंकि सस्ते होम लोन से घरों की मांग बढ़ती है, खासकर मध्यवर्ग और किफायती आवास खरीदारों में। इससे डेवलपर्स नए प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं, जिससे निर्माण गतिविधियां तेज होती हैं और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। आटोमोबाइल उद्योग को भी महत्वपूर्ण लाभ मिलता है, क्योंकि वाहनों पर मिलने वाले सस्ते कर्ज से दोपहिया, कार और व्यावसायिक वाहनों की बिक्री बढ़ सकती है, जिससे आटो-पार्ट्स और सहायक उद्योगों का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत होता है। महंगे कर्ज के बोझ तले दबे हुए एमएसएमई क्षेत्र को भी कम ब्याज दरों से राहत मिलती है। सस्ते कर्ज से वे अपनी परिचालन लागत घटाकर दक्षता बढ़ा सकते हैं, निवेश कर सकते हैं और विस्तार योजनाओं पर काम कर सकते हैं। स्टार्टअप्स के लिए भी कर्ज की उपलब्धता आसान होने से नवाचार को बढ़ावा मिलता है और प्रतिस्पर्धा में तेजी आती है। बैंकिंग क्षेत्र अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होता है, क्योंकि कर्ज की मांग बढ़ने से ऋण वितरण में सुधार होता है, जिससे लाभप्रदता और परिसंपत्ति गुणवत्ता बेहतर होती है। हालांकि बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे ब्याज दरों के अंतर को संतुलित रखते हुए वित्तीय स्थिरता और दीर्घकालिक विकास सुनिश्चित करें।

विकास की रफ्तार कायम रखने की चुनौती

रेपो दर में कटौती भले ही अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत लेकर आई हो, लेकिन इसके साथ कई ऐसे जोखिम भी जुड़े हैं, जिन पर निरंतर निगरानी जरूरी है। यदि इन जोखिमों को समय रहते नियंत्रित नहीं किया गया तो आने वाले महीनों में आर्थिक स्थिरता पर दबाव बढ़ सकता है। सबसे पहला बड़ा जोखिम है वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें। चूंकि कच्चा तेल भारत की आयात टोकरी का अहम हिस्सा है, लिहाजा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी कीमतों में तेजी घरेलू परिवहन, उत्पादन और उपभोग वस्तुओं की लागत बढ़ा सकती है। इससे महंगाई में उछाल आ सकता है, जिसके कारण भविष्य में ब्याज दरें और कम करना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा जोखिम रुपये की लगातार होती कमजोरी है। डालर के मुकाबले रुपया गिरने से आयातित वस्तुएं महंगी पड़ती हैं। भारत के कई उद्योग विदेशी कच्चे माल पर निर्भर हैं। इस कारण से उत्पादन लागत बढ़ती है और ऊंची कीमतें अंततः उपभोक्ताओं को झेलनी पड़ती हैं, जिससे महंगाई और व्यापार घाटे, दोनों में वृद्धि की आशंका है।

तीसरा खतरा वैश्विक भू-राजनीतिक तनावों से पैदा हुआ है। दुनिया के कई हिस्सों में जारी संघर्ष अंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्गों और सप्लाई चेन को बाधित कर रहे हैं। इसका सीधा असर भारत के निर्यात और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता पर पड़ रहा है, जिससे अनिश्चितता और निवेश में गिरावट का जोखिम बढ़ गया है। चौथा जोखिम अमेरिकी ब्याज दरों की नीति से जुड़ा है। देखा जाता है कि अमेरिका द्वारा दरों में वृद्धि किए जाने पर बड़ी मात्रा में पूंजी उभरते बाजारों से निकलकर अमेरिकी बाजारों में चली जाती है, जिससे रुपये पर दबाव पड़ता है और भारतीय शेयर बाजार में अस्थिरता पैदा होती है। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए आवश्यक है कि नीति-निर्माता सतर्क रहें और बदलती वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप ऐसी रणनीतियां अपनाएं, जो संतुलित, लचीली और दीर्घकालिक दृष्टि वाली हों, ताकि देश की आर्थिक स्थिरता कायम रहे।

–नृपेंद्र अभिषेक नृप

Dainik Jagaran Page No-9

पंजाब में सौर ऊर्जा बनी आर्थिक मजबूती और आत्मनिर्भरता की कुंजी

बिजली सब्सिडी से खजाने पर पड़ रहे भार को कम करने पर भी दिया जोर, गांवों में चल रहे ट्यूबवेल को भी सौर ऊर्जा नेटवर्क से जोड़ा

जागरण विशेष

कैलाश नाथ ● जागरण

चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने सौर ऊर्जा को केवल पर्यावरण संरक्षण तक सीमित न रखते हुए उसे आर्थिक मजबूती और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की कुंजी बना ली। दीर्घकालीन योजना, स्पष्ट नीति और जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन के चलते राज्य ने ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाई है। इन प्रयासों का सुफल है कि पंजाब को इस बार राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार में स्टेट परफार्मेंस श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार मिला है।

गत 14 दिसंबर को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के हाथों पुरस्कार ग्रहण करने वाले पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा इसका श्रेय सामूहिक प्रयास को देते हैं। उन्होंने कहा कि भवन क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। पंजाब एनर्जी डेवलपमेंट अथारिटी (पेडा) के अधिकारियों ने इस दिशा में सराहनीय कार्य किया है, जिसके अच्छे नतीजे आए। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से काम किया। सबसे पहले अपने सरकारी ढांचे से शुरुआत की। इसके तहत सरकारी भवनों पर 35 मेगावाट क्षमता वाले सोलर पैनल लगाए गए। इससे बिजली बिलों में बड़ी बचत हो रही है। ऐसे भवनों की संख्या ज्यादा है, जहां बिजली की कम खपत होती है। इनके लिए 25 मेगावाट के नए सोलर प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। बिजली का बहुत अधिक इस्तेमाल कृषि कार्य में होता है। कृषि बिजली पर सब्सिडी देने के कारण सरकारी खजाने पर बड़ा भार पड़ रहा था। एक अनुमान है कि किसानों को दी जाने वाली मुफ्त बिजली से सरकार पर वर्तमान में 20,200 करोड़ रुपये का आर्थिक बोझ आता है। इसके लिए भी सरकार ने चरणबद्ध तरीके से व्यावहारिक रास्ता अपनाया। सीधे कटौती के बजाय सौर ऊर्जा के जरिये वैकल्पिक समाधान चुना। गांव-गांव में लगे ट्यूबवेल को सौर ऊर्जा से जोड़ा। राज्य में सौर ऊर्जा से चलने वाले 18,000 पंप लगाए जा चुके हैं। इससे किसानों को सिंचाई के लिए टिकाऊ और भरोसेमंद ऊर्जा मिल रही है। किसानों को दिन के समय निर्बाध बिजली उपलब्ध हो रही है, वहीं राज्य की बिजली खपत और सब्सिडी बोझ में भी कमी आ रही है। इन सभी पहलों से अभी तक 1,200 करोड़ यूनिट बिजली की बचत की जा चुकी है।

औद्योगिक क्षेत्रों में भी हो रहा प्रयास

पंजाब सरकार के प्रयास केवल सोलर पंप या रूफटाप तक सीमित नहीं हैं। औद्योगिक व वाणिज्यिक क्षेत्रों में भी ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश हो रही है। एमएसएमई सेक्टर और वेरका प्लांट सहित कई संस्थानों में 185 ऊर्जा दक्ष मोटरें लगाने से बिजली की खपत में उल्लेखनीय कमी आई है। वाणिज्यिक भवनों में ऊर्जा संरक्षण भवन कोड को लागू किया जा रहा है। इसके तहत ऊर्जा दक्ष डिजाइन, आधुनिक निर्माण सामग्री और ऊर्जा बचत तकनीकों को अपनाया जा रहा है।

35 मेगावाट क्षमता वाले सौर ऊर्जा से सरकारी भवनों को जोड़ा जा चुका

25 मेगावाट के नए सोलर प्रोजेक्ट पर चल रहा है काम

18,000 सोलर पंप से किसानों को दिया जा रहा पानी

1,200 करोड़ यूनिट बिजली की हो चुकी है बचत

अमृतसर में नगर निगम की इमारत पर लगे सोलर पैनल ● जागरण

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से पुरस्कार ग्रहण करते पंजाब के मंत्री अमन अरोड़ा ● पंजाब सरकार

अतिरिक्त सामग्री पढ़ने के लिए स्कैन करें।

Dainik Jagaran Page No-7

1971 में पाकिस्तान पर विजय के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति भवन में 'परम वीर दीर्घा' का उद्घाटन

दीर्घा में प्रदर्शित किए गए सभी 21 परम वीर चक्र विजेताओं के चित्र

मोदी-शाह समेत विभिन्न नेताओं ने बहादुर सैनिकों को दी श्रद्धांजलि

<< राष्ट्रपति भवन में मंगलवार को परम वीर दीर्घा के उद्घाटन अवसर पर पूर्व सैन्य अधिकारी को शाल उढ़ाकर सम्मानित करतीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु। प्रेट

नई दिल्ली, प्रेट : 1971 में पाकिस्तान पर जीत के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में 'परम वीर दीर्घा' का उद्घाटन किया। इस गैलरी में सभी 21 परम वीर चक्र विजेताओं के चित्र प्रदर्शित किए गए हैं। परम वीर चक्र भारत का सबसे बड़ा सैन्य सम्मान है, जो युद्ध के दौरान वीरता, साहस और आत्म-बलिदान के असाधारण कार्यों के लिए दिया जाता है।

राष्ट्रपति भवन की जिस गैलरी में 'परम वीर दीर्घा' बनाई गई है, वहां पहले ब्रिटिश एडीसी के चित्र प्रदर्शित थे। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय नायकों के चित्र प्रदर्शित करने की यह पहल औपनिवेशिक सोच छोड़ने और भारत की संस्कृति, विरासत व परंपराओं की समृद्धता को गर्व के साथ अपनाने की दिशा में एक सार्थक कदम है। राष्ट्रपति ने एक्स पर एक पोस्ट में उन सैनिकों को श्रद्धांजलि भी दी जिन्होंने पाकपर जीत दिलाने में मदद की थी।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह दिवस साहसी सैनिकों की बहादुरी को सलाम करता है और उनके बेमिसाल जज्बे की याद दिलाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी देश के साहसी बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जाकर पुष्पांजलि अर्पित की। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि 1971 की जीत और हमारी सेना की कामयाबी हमेशा प्रेरणा बनी रहेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी 1971 की लड़ाई में अदम्य साहस प्रदर्शित करने वाले वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

Dainik Jagaran Page No-5

मनरेगा में बदलाव

केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा का नाम बदलते हुए जिस तरह उसके कई प्रविधान भी बदले और इससे संबंधित संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया, उस पर विपक्ष की आपत्ति पर आश्चर्य नहीं, क्योंकि अब सरकार की हर पहल का विरोध होता है। चूंकि मनरेगा का नया नाम विकसित भारत गारंटी फार रोजगार एंड अजीविका मिशन ग्रामीण अर्थात वीबी-जी राम जी कर दिया गया है, इसलिए विपक्ष अधिक हमलावर है। उसे यह कहने का अवसर मिल गया है कि सरकार महात्मा गांधी की उपेक्षा कर रही है। सरकार विपक्ष को यह अवसर उपलब्ध कराने से बच सकती थी, लेकिन शायद उसने ऐसा इसलिए किया ताकि इस अधिनियम में जो आमूल-चूल बदलाव प्रस्तावित हैं, उनका वह अधिक विरोध न कर सके। हालांकि सरकार ने नाम बदलने के औचित्य को सही ठहराया है, लेकिन इसमें संदेह है कि विपक्ष इससे संतुष्ट होगा। वैसे इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि पहली बार किसी योजना का नाम अथवा उसके प्रविधान नहीं बदले गए। मनरेगा भी मूल रूप में नरेगा थी। उसमें महात्मा गांधी का नाम बाद में जोड़कर मनरेगा किया गया था।

मनरेगा को जिस समय लागू किया गया, उस समय परिस्थितियां भिन्न थीं। सामाजिक सुरक्षा की सबसे प्रभावी योजना के रूप में प्रचलित इस अधिनियम में बदलाव की आवश्यकता एक लंबे समय से महसूस की जा रही थी। विपक्ष के नेता समय-समय पर बदलाव की इस आवश्यकता को रेखांकित भी करते थे, लेकिन अब वे किसी तरह के बदलाव के पक्ष में नहीं दिख रहे हैं। यह समझा जाना चाहिए कि मनरेगा से वे उद्देश्य पूरे होने में कठिनाई हो रही थी, जिनके लिए उसे लाया गया था। ऐसे मामले सामने आ रहे थे, जो यह बता रहे थे कि इस योजना में कई तरह की खामियां घर कर गई हैं। बतौर उदाहरण, जहां मजदूरी आधारित कार्य होने चाहिए थे, वहां मशीनों का इस्तेमाल होता था। इसी तरह ग्रामीण विकास के ठोस काम नहीं होते थे। अब सरकार ऐसी व्यवस्था करने जा रही है, जिससे गांवों में बुनियादी ढांचे का निर्माण हो सके। बदले हुए अधिनियम से ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका और आय के अवसरों को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया जा सकेगा। यह भी उल्लेखनीय है कि मजदूरी के दिवस बढ़ाने के साथ राज्यों को वर्ष में 60 दिन काम रोकने का अधिकार दिया गया है। इसकी मांग भी होती थी। सरकार इस अधिनियम में बदलाव के जरिये ग्रामीण विकास को एक ऐसी दिशा देना चाहती है, जिससे विकसित भारत के लक्ष्य को आसानी से हासिल किया जा सके। उचित यह होगा कि संसद में इस विधेयक के गुण-दोष के आधार पर व्यापक बहस हो ताकि इस अधिनियम को कहीं प्रभावी रूप दिया जा सके। सुधार की पहल के अतिरंजित विरोध से बचा जाना चाहिए।

Dainik Jagaran Page No-8

बिहार राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में सात निश्चय-तीन को दी गई स्वीकृति

राज्य ब्यूरो, जागरण • पटना

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में न्याय के साथ विकास पर आधारित साझा कार्यक्रम के संकल्प को दोहराते हुए अगले पांच वर्ष (2025-2030) में बिहार को देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए सात निश्चय -तीन के गठन को स्वीकृति दे दी गई। बैठक में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए अगले पांच वर्षों में 50 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही एक करोड़ नौकरी-रोजगार देने का विस्तृत रोड मैप भी बनाया गया है।

स्वयं मुख्यमंत्री ने साझा किए सातों निश्चय : मंत्रिमंडल की बैठक समाप्त होने के साथ ही स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश ने एक्स पोस्ट कर सात निश्चय के संकल्पों की जानकारी दी। लिखा कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्य में सुशासन के कार्यक्रमों के अन्तर्गत सात निश्चय (2015-2020) और सात निश्चय-2 (2020-2025) में

50 लाख करोड़ का निवेश, एक करोड़ रोजगार सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्ष में

नीतीश कुमार।

नीतीश बोले- बिहार को सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने की यह योजना

न्याय के साथ विकास से जुड़े निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के बाद बिहार को सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने के लिए अब सात निश्चय-3 कार्यक्रमों को लागू करने का निर्णय लिया गया है।

इसका उद्देश्य राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना करना है। इसके लिए कई कार्यक्रमों एवं योजनाओं को लागू किया गया है। इस कार्य को तय सीमा में पूरा करने के लिए अलग से युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया जा चुका है।

सरकार बोली

केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों में दी गई है यह जानकारी, पाकिस्तान से लगी सीमा का 6.75 प्रतिशत हिस्सा ही बाड़ लगाने के लिए रह गया है बाकी

भारत ने पाक से 93% व बांग्लादेश से 79% सीमा की सुरक्षित

नई दिल्ली, एएनआइ: भारत ने सुरक्षा मजबूत करने और घुसपैठ रोकने के उद्देश्य से पाकिस्तान-भारत अंतरराष्ट्रीय सीमा की 93 प्रतिशत लंबाई और बांग्लादेश-भारत सीमा की 79 प्रतिशत लंबाई की सीमा पर बाड़ लगा दी है। सरकार ने कहा है कि बाड़ घुसपैठ रोकने व राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाने की रणनीति का महत्वपूर्ण घटक है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2,289.66 किलोमीटर लंबी पाकिस्तान-भारत अंतरराष्ट्रीय सीमा में से 2,135.136 किलोमीटर पर बाड़ लगाई गई है, जो कुल सीमा का 93.25 प्रतिशत है। शेष 154.524 किलोमीटर या 6.75 प्रतिशत पाकिस्तान-भारत सीमा पर अभी बाड़ नहीं लगाई गई है। 4,096.70 किलोमीटर लंबी बांग्लादेश-भारत अंतरराष्ट्रीय सीमा में से 3,239.92 किलोमीटर पर बाड़ लगाई गई, जो सीमा का 79.08 प्रतिशत है। शेष 856.778 किमी या 20.92 प्रतिशत, बिना बाड़ के हैं। भारत-म्यांमार सीमा पर भी प्रगति हुई है, जिसकी कुल लंबाई 1,643 किलोमीटर है और "अब तक इस सीमा पर 9.214 किलोमीटर तक ही भौतिक बाड़ लगाई गई है।"

भारत-चीन सीमा पर कोई घुसपैठ दर्ज नहीं: केंद्र सरकार ने संसद को सूचित किया कि 2014 से भारत-चीन सीमा पर "कोई घुसपैठ" का मामला दर्ज नहीं हुआ है, जबकि इसी अवधि में सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल और भूटान के साथ भारत की सीमाओं पर 23,926 घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है। जबकि जनवरी से नवंबर 2025 के बीच इन सीमाओं से 3,120 घुसपैठिए गिरफ्तार किए गए। नित्यानंद राय ने लोकसभा में बताया कि भारत-बांग्लादेश सीमा पर सबसे अधिक गिरफ्तारियां हुईं। इसके बाद म्यांमार, पाकिस्तान और नेपाल-भूटान की सीमाएं रहीं। 2014 से अब तक के सालाना आंकड़े यह दर्शाते हैं कि भारत के पश्चिमी और पूर्वी सीमाओं पर घुसपैठ के प्रयास लगातार जारी हैं।

प्रतीकात्मक

माओवादी हिंसा 15 वर्षों में 89 प्रतिशत घटी

माओवादी हिंसा से जुड़ी घटनाएं 2010 में 1,936 की उच्चतम संख्या से घटकर 2025 में 222 पर हैं, जो 89 प्रतिशत की कमी दर्शाती है। नित्यानंद राय ने लोकसभा में बताया कि 2015 में लागू की गई "राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना" के प्रभावी कार्यान्वयन के कारण हिंसा में कमी आई है, जिससे नागरिकों व सुरक्षा कर्मियों की मौतें भी 2010 में 1,005 से घटकर 2025 में 95 हो गईं, जो 91 प्रतिशत की कमी है। सरकार का माओवादी विचारधारा के मूल कारणों को दूर कर रहा है।

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में 438 आत्महत्याएं: केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, असम राइफल्स और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) के कर्मियों में पिछले तीन वर्षों में कुल 438 आत्महत्याएं और सात भाई-भाई की हत्या के मामले दर्ज किए। आत्महत्या की संख्या 2023 में 157 से घटकर 2025 में 133 हो गई, जबकि 2023 में भाई-भाई की हत्या के दो मामले दर्ज हुए। 2024 में एक और 2025 में चार ऐसे मामले सामने आए। सीआरपीएफ में सबसे अधिक 159 आत्महत्याएं दर्ज की गईं। बीएसएफ में 120 व सीआइएसएफ में 60 आत्महत्याएं हुईं। 2014 से 2025 के बीच केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों व असम राइफल्स के कुल 23,360 कर्मियों ने इस्तीफा दिया।

****

Dainik Jagaran Page No-3

इंश्योरेंस सेक्टर में 100% एफडीआइ का रास्ता साफ

लोस ने दी मंजूरी, अभी एफडीआइ की अधिकतम सीमा थी 74 प्रतिशत

धोखाधड़ी करने पर कंपनी और इंटरमीडियरिज पर 10 करोड़ तक का होगा जुर्माना

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सबका बीमा, सबकी रक्षा संशोधन विधेयक 2025 को मंगलवार को लोकसभा ने अपनी मंजूरी दे दी। इसके साथ ही इंश्योरेंस सेक्टर में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) का रास्ता साफ हो गया। अभी तक इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआइ की अधिकतम सीमा 74 प्रतिशत है। सरकार ने 2047 तक देश के हर व्यक्ति को इंश्योरेंस के दायरे में लाने का लक्ष्य रखा है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बिल को लोकसभा में पेश करते हुए कहा, इंश्योरेंस सेक्टर में 100 प्रतिशत एफडीआइ की इजाजत से इस सेक्टर में पूंजी का प्रवाह बढ़ेगा। कंपनियों की संख्या बढ़ेगी। विभिन्न प्रकार के नए-नए उत्पाद आएंगे। इन सबसे कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। लोगों को सस्ते दाम पर इंश्योरेंस उपलब्ध हो सकेंगे। यह भी साफ किया कि इंश्योरेंस प्रीमियम की राशि देश से बाहर ले जाने की इजाजत नहीं होगी। इंश्योरेंस कराने वालों के हितों को ध्यान में रखते हुए बीमा नियामक को अब अधिक अधिकार दिया जा रहा है।

लोकसभा में मंगलवार को बीमा संशोधन विधेयक पेश करने के दौरान बोलतीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। प्रेट्र

कंपनी या इंटरमीडियरिज यदि ई के नाम पर कोई धोखाधड़ी या कमाई करते हैं तो उन पर 10 करो का जुर्माना किया जाएगा। अभी यह एक करोड़ तक की है। इंश्योरेंस बेचने वाली सभी कंपनियों को नाम में इंश्योरेंस शब्द का इ करना अनिवार्य होगा ताकि लोगों वे कंपनी को लेकर कोई गलतफहमी बिभिन्न प्रकार के इंश्योरेंस के लिए बार केवाईसी नहीं करना होगा। ई कराने वालों के डाटा को डाटा कानून के तहत गोपनीय रखना होग

वित्त मंत्री ने कहा,इंश्योरेंस से पारदर्शिता को और बढ़ाने के लिए भी नए नियम को लाने से पहले सार्वजनिक रूप से नियामक को विचार-विमर्श करना अनिवार्य किया जा रहा है। इंश्योरेंस धारकों को उनके अधिकार और इंश्योरेंस के फायदे बताने, उन्हें शिक्षित व जागरूक करने के लिए एक फंड का निर्माण किया जाएगा। यह इंश्योरेंस कंपनियों से वसूले जाने वाले जुर्माने की राशि से बनाया जाएगा। सीतारमण ने कहा, इंश्योरेंस सेक्टर में देश में अभी 74 कंपनियां हैं। इनमें से 10 कंपनियों में 26

अगले वित्त वर्ष में भी 7.5 प्रतिशत रहेगी भारत की आर्थिक वृद्धि दर

- एक्सिस बैंक ने इकोनमी आउटलुक 2026 में जताया अनुमान
- सरकारी खर्च पर दबाव कम होने से इकोनमी में तेज वृद्धि होने की संभावना जताई

मुंबई, आइएएनएस: भारत की आर्थिक वृद्धि आने वाले वर्षों में तेज होगी और मजबूत बनी रहेगी। इसके साथ ही अगले वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक वृद्धि 7.5 प्रतिशत रह सकती है। एक्सिस बैंक के इकोनमी आउटलुट 2026 में यह बात कही गई है।

एक्सिस बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री और एक्सिस कैपिटल के डिप्टिक शोध प्रमुख नीलकंठ मिश्रा का कहना है कि यह वृद्धि संरचनात्मक और नियामक सुधारों, कम उधारी लागत, तेज पूंजी निर्माण और नीतिगत ढील से मिलने वाले चक्रीय समर्थन के कारण होगी। मिश्रा और बैंक की आर्थिक शोध टीम का मानना है कि इकोनमी में सुस्ती को देखते हुए महंगाई के दबाव के बिना भी स्थान से बेहतर वृद्धि बनी रह सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकारी खर्च पर दबाव कम होने और अनुकूल मौद्रिक नीतियों के चलते अर्थव्यवस्था में 7.5 प्रतिशत से ज्यादा की तेज वृद्धि हो सकती है। साथ ही, सरल नियमों और सुधारों से आने वाले समय में विकास को और मजबूती मिलेगी। बेहतर वित्तीय स्थिति, पूंजी की कम लागत और उच्च क्षमता उपयोग (जिससे नए पूंजीगत निवेश की जरूरत बनेगी) के कारण अगले वित्त वर्ष में पूंजीगत व्यय में बढ़ोतरी होने की संभावना है। वित्त वर्ष 2026-27 में औसत महंगाई करीब चार प्रतिशत रहने की संभावना है। पिछले 18 महीनों से महंगाई लगभग तीन प्रतिशत पर स्थिर है।

उनके परिजनों तक लौटाने का अभियान 500 जिलों में अक्टूबर में शुरू किया गया था। दो माह में इस अभियान के तहत 2000 करोड़ रुपये लोगों को लौटाए जा चुके हैं।

लोकसभा ने 71 पुराने कानूनों को खत्म करने के लिए विधेयक को दी मंजूरी

- कानून मंत्री मेघवाल बोले- यह कदम नागरिकों के जीवन को बनाएगा सरल
- सुगम मोदी सरकार अब तक, 1,562 पुराने और अप्रचलित कानूनों को खत्म कर चुकी

नई दिल्ली, प्रेट्र: लोकसभा ने मंगलवार को 71 पुराने और अप्रचलित कानूनों को निरस्त या संशोधित करने के लिए एक विधेयक को पारित किया। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा,यह कदम नागरिकों के जीवन को सरल व सुगम बनाने में सहायक साबित होगा। मई 2014 से मोदी सरकार लगातार उपनिवेशी युग के पुराने व अप्रचलित कानूनों को समाप्त कर रही है। ये सुधार उपनिवेशी मानसिकता से मुक्ति की दिशा में एक कदम हैं। अब तक, 1,562 पुराने व अप्रचलित कानून निरस्त किए जा चुके हैं। इस प्रस्तावित विधेयक को संसद की मंजूरी मिल जाने पर निरस्त किए जाने वाले कानूनों की कुल संख्या 1,633 हो जाएगी।

विधेयक पर चर्चा का उत्तर देते हुए मेघवाल ने बताया कि प्रस्तावित कानून का उद्देश्य पुराने कानूनों को हटाना, कानून बनाने की प्रक्रिया में आई त्रुटियों को सुधारना व कुछ कानूनों के भेदभावपूर्ण पहलुओं को समाप्त करना है। मोदी सरकार में कानून की किताबों में कोई भेदभाव नहीं हो सकता। कहा, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के तहत यदि कोई हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन या पारसी वसीयत बनाता है तो उसे प्रमाणित करना जरूरी है, जबकि अन्य समुदाय पर ऐसा प्रविधान लागू नहीं होता। यह विधेयक 71 अधिनियमों को निरस्त करेगा जिसमें भारतीय ट्रामवे अधिनियम, 1886, लेवी शुगर प्राइस इक्वलाइजेशन फंड अधिनियम, 1976, व भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (कर्मियों की सेवा शर्तों का निर्धारण) अधिनियम, 1988 शामिल हैं। विधेयक चार अधिनियमों में संशोधन करेगा, जिसमें सामान्य धाराएं अधिनियम, 1897, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 शामिल हैं ताकि पंजीकृत डाक के लिए शब्दावली को अपडेट किया जा सके। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियममें कुछ मामलों में वसीयत की मान्यता के लिए अदालतों से अनुमोदन की जरूरत को खत्म किया जा सके। विधेयक आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में ड्राफ्टिंग त्रुटि सही करने को भी संशोधन करेगा। कांग्रेस, सपा व तृकां ने विधेयक की आलोचना करते हुए कहा, यह लोगों के लाभ के लिए नहीं है।

Dainik Jagaran Page No-3

अहम टिप्पणी

दिल्ली हाई कोर्ट नेकहा- मकान मालिक व किराएदार विवाद के कारण बिजली आपूर्ति से नहीं किया जा सकता वंचित, एक किराएदार की याचिका पर अदालत ने सुनाया अहम निर्णय

'संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत बिजली एक मौलिक अधिकार'

विनीत त्रिपाठी • जागरण

नई दिल्लीः बिजली आपूर्ति काटने के विरुद्ध दायर एक याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय पारित करते हुए कहा कि बिजली आपूर्ति संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। अदालत ने कहा कि किसी संपत्ति पर कानूनी कब्जा रखने वाले व्यक्ति को सिर्फ मकान मालिक-किराएदार विवाद के कारण इससे वंचित नहीं किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि बिजली एक बुनियादी जरूरत है और जब तक याचिकाकर्ता संबंधित संपत्ति पर कब्जे में है, तब तक उसे बिजली की सुविधा से वंचित नहीं किया जा सकता।

बीसईएस राजधानी पावर लिमिटेड को याचिकाकर्ता को बिजली आपूर्ति का निर्देश देते हुए अदालत ने उक्त टिप्पणी की। याचिकाकर्ता पश्चिमी दिल्ली में एक रिहायशी संपत्ति की तीसरी मंजिल पर बिजली आपूर्ति बहाल करने की मांग की थी। पीठ ने आगे कहा कि किसी भी नागरिक से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह बिजली जैसी बुनियादी जरूरतों के बिना जीवन जिए।

दिल्ली हाई कोर्ट। फाइल

याचिकाकर्ता मैकी जैन की याचिका के अनुसार दावा किया कि वह 2016 से रजिस्टर्ड लीज डीड के तहत नई दिल्ली में एक संपत्ति के किराएदार के तौर पर कब्जे में हैं। बकाया रकम चुकाने के बावजूद नवंबर 2025 में उसके मकान की बिजली काट दिए जाने के बाद मैकी जैन ने हाई कोर्ट का रुख किया था।

परिसर में बिजली का मीटर मकान मालिकों के नाम पर रजिस्टर्ड था, लेकिन किराए वाले हिस्से में लगातार बिजली आपूर्ति की जा रही थी और बिल का भुगतान नियमित रूप से किया जा रहा था। अस्थायी वित्तीय कठिनाई के कारण याचिकाकर्ता सितंबर और अक्टूबर 2025 के बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पाया। इसके कारण 28 नवंबर 2025 को बिजली काट दी गई और मीटर हटा दिया गया। जैन ने दावा किया कि उसी दिन बकाया रकम चुका दी गई थी, लेकिन बीएसईएस ने तब तक आपूर्ति बहाल करने से इन्कार कर दिया जब तक कि वह मकान मालिकों से एनओसी न ले आए। हालांकि, मकान मालिकों ने एनओसी देने से मना कर दिया था। बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि मकान मालिक बिजली कनेक्शन के रजिस्टर्ड उपभोक्ता थे और बकाया भुगतान न करने के कारण आपूर्ति काट दी गई थी।

****

स्वजन व रिश्तेदारों से पत्नी को मिले तोहफे को नहीं माना जा सकता आय का स्रोतः

जासं, नई दिल्ली: पत्नी को रखरखाव भत्ता देने के पारिवारिक न्यायालय के निर्णय को चुनौती देने वाली पति की याचिका को खारिज करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्णय सुनाया कि स्त्रीधन, विरासत में मिली संपत्ति या पत्नी को उसके स्वजन या रिश्तेदारों से मिले तोहफों को आय का स्रोत नहीं माना जा सकता। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने कहा कि रखरखाव भत्ते के दावे का आकलन पत्नी के मायके वालों की वित्तीय स्थिति के आधार के बजाय उसकी मौजूदा कमाई की क्षमता के आधार पर किया जाना चाहिए।

Dainik Jagaran Page No-2

आइसिस से प्रेरित था बोंडी बीच पर आतंकी हमला : आस्ट्रेलियाई पुलिस

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

आस्ट्रेलिया में सिडनी के बोंडी बीच पर हनुक्का उत्सव मना रहे यहूदियों पर हमला करने वाले पिता-पुत्र साजिद अकरम व नवीद अकरम इस्लामिक स्टेट (आइसिस) से प्रेरित थे। उनकी कार से घर में बने आइसिस के दो झंडे बरामद हुए हैं। दोनों ने नवंबर में फिलीपींस की यात्रा भी की थी। साजिद ने भारत व नवीद ने आस्ट्रेलिया के पासपोर्ट पर यह यात्रा की थी। रविवार को हुए उक्त आतंकी हमले में 15 लोग मारे गए थे।

रायटर के अनुसार,आस्ट्रेलियाई पुलिस ने मंगलवार को कहा,हमलावर पिता-पुत्र की फिलीपींस यात्रा का मकसद क्या था, इसकी जांच की जा रही है। फिलीपींस के आव्रजन अधिकारियों ने बताया कि पिता-पुत्र एक नवंबर को मनीला, फिर देश के दक्षिण में डावाओ गए थे। 28 नवंबर को वहां से चले गए थे। साजिद भारतीय पासपोर्ट (आस्ट्रेलिया में वीजा पर होने के कारण) पर गया था, जबकि नवीद आस्ट्रेलियाई पासपोर्ट (जन्म से आस्ट्रेलियाई नागरिक होने के कारण) पर था। उन्होंने कहा, यह पक्का नहीं है कि वे किसी आतंकी समूह से जुड़े थे या उन्होंने देश में प्रशिक्षण लिया था। हालांकि आस्ट्रेलियाई मीडिया के अनुसार, साजिद व नवीद को फिलीपींस में ही कहीं पर हथियार चलाने की ट्रेनिंग मिली थी। ज्ञात हो,आइसिस से जुड़े नेटवर्क फिलीपींस में सक्रिय हैं। 2017 के मारावी घेराबंदी के दौरान उनका काफी प्रभाव था।

आस्ट्रेलियाई फेडरल पुलिस कमिश्नर क्रिसी बैरेट ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, शुरुआती संकेत आइसिस से प्रेरित आतंकी हमले की ओर इशारा करते हैं। ये उन लोगों का काम है जो किसी धर्म से नहीं, एक आतंकी संगठन से जुड़ाव रखते हैं। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भी कहा, ये बातें सुबूतों पर आधारित हैं, जो उसकी कार से बरामद हुए हैं। इस बीच, नवीद के सिडनी के एक उपनगरीय इलाके में रेलवे स्टेशनों के बाहर इस्लाम का प्रचार करते हुए वीडियो सामने आए हैं।

- कहा- हमलावर पिता-पुत्र साजिद-नवीद ने भारतीय व आस्ट्रेलियाई पासपोर्ट पर की थी फिलीपींस की यात्रा
- सिडनी के बोंडी बीच पर हनुक्का उत्सव मना रहे यहूदियों पर गोलीबारी में मारे गए थे 15 लोग

न्यू साउथ वेल्स पुलिस मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन के दौरान(बाएं से) आस्ट्रेलियाई फेडरल पुलिस कमिश्नर क्रिसी बैरेट और पीएम एंथनी अल्बनीज। रायटर

वह हिंसा के रास्ते पर कैसे चला गया इसकी हो रही जांच पेज>>11

Dainik Jagaran Page No-1

Useful For Mains

प्रदूषण की परतें और किसानों की मुश्किल

जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई एक वैश्विक प्रयास है, जिसमें समाज के सभी क्षेत्रों के सहयोग की आवश्यकता है। किसानों को कठघरे में खड़ा करने के बजाय हमें पर्यावरण और कृषि, दोनों जरूरतों को पूरा करने वाले समाधान खोजने की जरूरत है।

केसी त्यागी
बिशन नेहवाल

दिल्ली समेत आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण हाहाकार मचा हुआ है। कभी दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एक्यूआइ गंभीर श्रेणी को पार कर जाता है तो कभी दिन का उच्चतम तापमान सारे कीर्तिमान ध्वस्त कर देता है। वायु प्रदूषण के कारण बीमारियों में काफी वृद्धि हुई है। एक्यूआइ के लिए कई बार लोग पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों द्वारा जलाई जाने वाली पराली को लगभग एकतरफा तौर पर दोषी ठहराना शुरू कर देते है। राज्य सरकारों द्वारा भी आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। जबकि सिर्फ दिल्ली में नहीं, बल्कि देश के कई अन्य शहरों में भी वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा है।

यह समझना आवश्यक है कि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के लिए केवल किसानों को दोषी ठहराना एक अदूरदर्शी और अप्रभावी दृष्टिकोण है। हमें धुएं वाले खेतों से परे देखना चाहिए और उन आंकड़ों की जांच करनी चाहिए, जो हमारी जहरीली हवा के वास्तविक कारणों को रेखांकित करते हैं। विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र यानी सीएसई की एक रपट ने इस बात की पुष्टि की है कि दिल्ली के लगातार कोहरे के पीछे का असली कारण दूर की पराली नहीं, बल्कि सड़कों पर बेहिसाब वाहन और स्थानीय, अनियंत्रित कारक हैं। इसकी पुष्टि दिल्ली सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर में वायु प्रदूषण की स्थिति पर 2018 की संसदीय समिति की रपट से भी होती है, जिसने प्रदूषण में योगदान देने वाले प्रमुख कारकों का विस्तार से वर्णन किया था। इस रपट के अनुसार, भारी मात्रा में प्रदूषक दरअसल वाहन उत्सर्जन, निर्माण और औद्योगिक उत्सर्जन, कचरा जलाने से निकलने वाले धुएं और सड़क की धूल से निकलते हैं। यह अक्सर अनियंत्रित, शहरी और औद्योगिक विस्तार की पहचान हैं।

यह विडंबना ही है कि दिल्ली में प्रदूषण के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर के पराली के धुएं को जिम्मेदार बताया जाता है, लेकिन जब किसान उचित मुआवजा पाने के लिए संघर्ष करते हैं, तो उनकी दुर्दशा अक्सर तहसील स्तर पर भी दर्ज नहीं हो पाती है। तथ्य यह है कि पराली जलाना तेज हवा वाले दिनों को छोड़कर, समग्र वार्षिक प्रदूषण भार में मामूली योगदान देता है। इसके अलावा, किसान इसका सहारा इसलिए लेते हैं, क्योंकि यह आर्थिक अस्तित्व और तार्किक मजबूरी का विषय है। वे धान की कटाई और गेहूं की अगली फसल की बुआई के बीच एक गंभीर रूप से सीमित समय सीमा का सामना करते हैं, जिससे यांत्रिक अवशेष प्रबंधन का महंगा और समय लेने वाला विकल्प पर्याप्त सरकारी समर्थन के बिना आर्थिक रूप से अव्यावहारिक हो जाता है। उन्हें दोष देना समाधान नहीं है।

यह सही है कि कृषि भी ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का एक स्रोत है। मुख्य रूप से मीथेन (सीएच4) और नाइट्रस आक्साइड (एन2ओ) के रूप में, जो विभिन्न कृषि गतिविधियों के दौरान निकलते हैं। पशुधन खेती, चावल की खेती और सिंथेटिक उर्वरकों का उपयोग इन उत्सर्जनों में प्रमुख योगदानकर्ताओं में से हैं। हालांकि इन तथ्यों को स्वीकार करना जितना महत्त्वपूर्ण है, कृषि उत्सर्जन की जटिलताओं को पहचानना भी उतना ही आवश्यक है। किसान समाज की रीढ़ हैं, जो हमारा भोजन उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार हैं। कई किसान पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए कम जुताई, फसल चक्र और सटीक

कृषि जैसी टिकाऊ प्रथाओं को अपना रहे हैं। वे समझते हैं कि दीर्घकालिक कृषि स्थिरता के लिए एक स्वस्थ वातावरण आवश्यक है।

भारत में कृषि मात्र जीविकोपार्जन का साधन नहीं, बल्कि एक जीवन पद्धति है। किसान मौसम के अप्रत्याशित मिजाज, बढ़ती लागत, बदलती बाजार मांगों और पैदावार बढ़ाने के लगातार दबाव से जूझते हैं। अधिकांश किसान पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। वे दुनिया की बढ़ती आबादी को खाना खिलाते हुए बस जीविकोपार्जन करने की कोशिश कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन में उनकी भूमिका के लिए किसानों को दोषी ठहराने के बजाय, टिकाऊ कृषि पद्धतियों के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना अधिक रचनात्मक दृष्टिकोण है। कई किसान पर्यावरण के अनुकूल तरीकों को अपनाने के इच्छुक हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें अक्सर प्रशिक्षण से लेकर वित्तीय सहयोग जैसे समर्थन की आवश्यकता होती है।

> **भारत में कृषि मात्र जीविकोपार्जन का साधन नहीं, बल्कि एक जीवन पद्धति है। यह एक ऐसी विधा है, जिसमें सूक्ष्म जीवों के पोषण के लिए भी व्यवस्था की गई है। मगर आज यह अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। किसान मौसम के अप्रत्याशित मिजाज, बढ़ती लागत, बदलती बाजार मांगों और पैदावार बढ़ाने के लगातार दबाव से जूझते हैं। अधिकांश किसान पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। वे दुनिया की बढ़ती आबादी को खाना खिलाते हुए बस जीविकोपार्जन करने की कोशिश कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन में उनकी भूमिका के लिए किसानों को दोषी ठहराने के बजाय, टिकाऊ कृषि पद्धतियों के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना अधिक रचनात्मक दृष्टिकोण है।**

किसानों को कृषि उत्पादन का समर्थन करने के लिए ज्यादातर देशों में अक्सर अपनी सरकारों से सबसिडी और प्रोत्साहन मिलता है। यह सबसिडी दायरे और प्रकृति में व्यापक रूप से भिन्न हो सकती है, लेकिन इनका उद्देश्य आमतौर पर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, किसानों के लिए सुरक्षा जाल प्रदान करना और कृषि स्थिरता को बढ़ावा देना है। आलोचकों का तर्क होता है कि कुछ सबसिडी अनजाने में वैसे चलन को प्रोत्साहित करती है, जो उच्च उत्सर्जन को जन्म देती हैं, जैसे सिंथेटिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग। समझना आवश्यक है कि ये सबसिडी मुख्य रूप से आर्थिक और खाद्य सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए बनाई गई है। हालांकि अब सरकारें टिकाऊ कृषि पद्धतियों के महत्त्व को पहचान रही हैं। अब प्रोत्साहनों को कार्बन उत्सर्जन को कम करने और पर्यावरण के अनुकूल तरीकों को बढ़ावा देने की दिशा में निर्देशित किया जा रहा है।

इसके अलावा, सरकार द्वारा अधिक टिकाऊ कृषि प्रौद्योगिकियों के लिए अनुसंधान और विकास में निवेश करना आवश्यक है। इसमें कम उत्सर्जन वाले पशुधन चारे का विकास और खेतों पर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना शामिल है। सटीक कृषि जैसे नवाचार, जिसमें फसल और पशुधन उत्पादन को अनुकूलित करने के लिए डेटा और प्रौद्योगिकी का उपयोग शामिल है, संसाधन अपव्यय और उत्सर्जन को काफी कम कर सकते हैं।

किसानों के टिकाऊ कृषि की ओर कदम बढ़ाने के लिए प्रभावी नीतियां महत्त्वपूर्ण हैं। सरकारों को नियमों और प्रोत्साहनों के माध्यम से पर्यावरण-अनुकूल खेती के तरीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और वित्तीय रूप से समर्थन देना जारी रखना चाहिए। इसमें जैविक खेती, कृषि वानिकी और सटीक कृषि जैसी प्रथाओं के लिए प्रोत्साहन शामिल हैं, जिनमें उत्सर्जन को कम करने की क्षमता है। कृषि पद्धतियों को आकार देने में उपभोक्ता भी भूमिका निभाते हैं। टिकाऊ और पर्यावरण के प्रति जागरूक खेतों से उत्पाद चुनकर वे इस तरह के चलन को प्रोत्साहित कर सकते हैं और बाजार में बदलाव में योगदान दे सकते हैं। साथ ही शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम किसानों को उनकी प्रथाओं के पर्यावरणीय प्रभाव और अधिक टिकाऊ दृष्टिकोण में परिवर्तन के लाभों को समझने में मदद कर सकते हैं।

जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई एक वैश्विक प्रयास है, जिसमें समाज के सभी क्षेत्रों के सहयोग की आवश्यकता है। योगदानकर्ता और संभावित शमनकर्ता, दोनों के रूप में किसानों की बहुमुखी भूमिका को पहचानना आवश्यक है। किसानों को कठघरे में खड़ा करने के बजाय हमें पर्यावरण और कृषि, दोनों जरूरतों को पूरा करने वाले समाधान खोजने के की जरूरत है। सरकारों, समाजों और कृषि उद्योग को अधिक टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल कृषि पद्धतियों में परिवर्तन की सुविधा के लिए आवश्यक समर्थन, प्रोत्साहन और शिक्षा प्रदान करने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है। यह सहयोगात्मक दृष्टिकोण पर्यावरण संरक्षण के साथ खाद्य उत्पादन की आवश्यकता को संतुलित करने में मदद कर सकता है। एक निष्पक्ष दृष्टिकोण अधिक टिकाऊ भविष्य की दिशा में सामूहिक रूप से काम करते समय किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करता है।

Jansatta Page No-6

पर्यावरण मंत्रालय ने संसद में दी जानकारी | प्रदूषण संकट | धान की खेती, कपास-चाय बगान जैसे कार्य करने वालों पर असर

जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक ग्रामीण महिलाएं प्रभावित

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 16 दिसंबर।

पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह बताया कि भारत में कुल 67 फीसद महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा जलवायु संवेदनशील क्षेत्र कृषि है, जिसमें कुल 30 फीसद किसान और लगभग 43 महिला कृषि श्रमिक हैं। भारत द्वारा 2023 में संयुक्त राष्ट्र की जलवायु संस्था को प्रस्तुत किए गए तीसरे राष्ट्रीय प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया गया है कि जलवायु की चरम स्थितियां और जलवायु परिवर्तन महिलाओं पर काम के बोझ को बढ़ा रहे हैं। प्रदूषण के प्रभाव से महिलाएं अधिक प्रभावित है।

देश में जलवायु परिवर्तन का असर सर्वाधिक महिलाओं पर पड़ रहा है। यह असर पारंपरिक रूप से ग्रामीण महिलाओं से जुड़े हैं, जो कि धान की खेती, कपास और चाय के बागान और मछली पकड़ने जैसे कार्य करने वाली महिलाओं पर देखा गया है। पर्यावरण मंत्रालय ने संसद में एक लिखित सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। बताया गया है कि भारत में कुल 67 फीसद महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा जलवायु संवेदनशील क्षेत्र कृषि है, जिसमें कुल 30 फीसद किसान और लगभग 43 महिला कृषि श्रमिक हैं।

पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह के यह जवाब दिया है। उन्होंने बताया कि भारत द्वारा 2023 में संयुक्त राष्ट्र की जलवायु संस्था को प्रस्तुत किए गए तीसरे राष्ट्रीय प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया गया है कि जलवायु की चरम स्थितियां और जलवायु परिवर्तन महिलाओं पर काम के बोझ को बढ़ा रहे हैं। प्रदूषण के प्रभाव से महिलाएं अधिक प्रभाावित है। कहा कि अनियमित वर्षा की बार-बार होने वाली घटनाएं और चरम मौसम की घटनाओं की बढ़ती संभावना कृषि उपज के नुकसान का कारण बन सकती हैं।

उन्होंने कहा कि फसल के नुकसान से महिलाएं सबसे अधिक प्रभावित होती हैं, क्योंकि फसल अक्सर उनकी आजीविका और आय का एकमात्र स्रोत होती है। सरकार ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से महिलाओं को होने वाले खतरे को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कम करने के लिए कई योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए हैं। इनमें जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय कार्यक्रम, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत मातृ एवं शिशु ट्रैकिंग प्रणाली शामिल हैं।

सरकार ने कहा कि ये योजनाएं जलवायु संबंधी जोखिमों के प्रति महिलाओं की संवेदनशीलता और जोखिम को कम करती हैं, साथ ही उनकी अनुकूलन क्षमता को बढ़ाती हैं। सरकार के मुताबिक जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने के लिए सरकार कई अहम योजनाओं पर काम कर रही है। सरकार ने राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना में सौर ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, पानी, कृषि, स्वास्थ्य, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र हरित भारत और जल वायु परिवर्तन जैसे मिशन इसमें शामिल किए हैं। इसके लिए 34 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों ने केंद्र सरकार के कार्यक्रम की तर्ज पर राज्य कार्य जलवायु परिवर्तन योजना भी तैयार की है।

Jansatta Page No-14

1.5 डिग्री तापमान वृद्धि से तेजी से पिघल रहे ग्लेशियर

अध्ययन ▶ हर साल लगभग 2,000 ग्लेशियर गायब हो जाएंगे, 2055 तक हर साल लगभग 4,000 ग्लेशियर होंगे खत्म

स्विट्जरलैंड और बेल्जियम के विभिन्न संस्थानों के शोधकर्ताओं ने दी जानकारी

नई दिल्ली, प्रेट : पूरी दुनिया पर तापमान वृद्धि का असर देखने को मिल रहा है। एक अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि दुनिया भर में ग्लेशियरों के पिघलने की दर 2041 में चरम पर पहुंच सकती है, जिसमें 1.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग के तहत हर साल लगभग 2,000 ग्लेशियर गायब हो जाएंगे। स्विट्जरलैंड व बेल्जियम के विभिन्न संस्थानों के शोधकर्ताओं ने बताया कि 2041 के बाद जब छोटे ग्लेशियर गायब हो चुके होंगे, तब वार्षिक नुकसान में कमी आएगी।

चार डिग्री सेल्सियस वृद्धि पर चरम 2055 में होगा : इस बारे में नेचर क्लाइमेट चेंज जर्नल पत्रिका में अध्ययन प्रकाशित किया गया। इसमें लेखकों ने अनुमान लगाया है कि चार डिग्री की वैश्विक तापमान वृद्धि के तहत चरम 2055 में होगा, लेकिन हर साल लगभग 4,000 ग्लेशियर के खत्म होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि गर्म मौसम में छोटे और बड़े दोनों तरह के ग्लेशियर पूरी तरह से गायब हो जाएंगे।

कम ऊंचाई पर या भूमध्य रेखा के पास छोटे ग्लेशियर वाले क्षेत्र खास तौर पर संवेदनशील पाए गए, इनमें आल्प्स, काकेशस (यूरोप व एशिया के बीच), राकी पर्वत (उत्तरी अमेरिका) और एंडीज (दक्षिण अमेरिका) के कुछ हिस्से और कम अक्षांशों में स्थित अफ्रीकी पर्वत श्रृंखलाएं शामिल हैं। ईटीएच ज्यूरिख के ग्लेशियोलाजी चेयर के शोधकर्ता लैंडर वैन ट्रिच्ट ने कहा, इन क्षेत्रों में दस से बीस सालों में आधे से ज्यादा ग्लेशियरों के गायब होने की

तेजी से पिघल रहे ग्लेशियर। फाइल राइटर

उम्मीद है।

जलवायु कार्रवाई की आवश्यकता : वैन ट्रिच्ट ने कहा, पहली बार हमने यह बताया कि धरती पर हर एक ग्लेशियर कब गायब हो जाएगा। सहायक लेखक और ईटीएच ज्यूरिख में ग्लेशियोलाजी के प्रोफेसर डैनियल फारिनोटी ने कहा, ये नतीजे इस बात पर जोर देते हैं कि कितनी तेजी से जलवायु कार्रवाई की आवश्यकता है।

गायब होने वाले ग्लेशियरों की संख्या में वृद्धि : उन्होंने कहा कि मध्यम आकार के ग्लेशियरों की प्रचुरता के कारण इस क्षेत्र में मध्य सदी के आसपास ग्लेशियरों के विलुप्त होने का चरम देखने को मिल सकता है, जो वैश्विक पैटर्न को मजबूती से दर्शाता है। लेखकों ने लिखा, यहां तीन वैश्विक ग्लेशियर माडल का इस्तेमाल कर हम दुनिया भर में गायब होने वाले ग्लेशियरों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी का अनुमान लगाते हैं, जो 2041 और 2055 के बीच चरम पर होगी, जिसमें सालाना (लगभग) 4,000 ग्लेशियर गायब हो जाएंगे। अध्ययन में पाया गया कि चार डिग्री सेल्सियस ग्लोबल तापमान बढ़ने पर 2100 तक सिर्फ 18,000 ग्लेशियर बचेंगे, जबकि 1.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग पर लगभग 100,000 ग्लेशियर बचेंगे।

.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग होने पर 12 प्रतिशत ग्लेशियर बचेंगे : यूरोप की सबसे ऊंची और सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला आल्प्स के लिए पर 1.5 डिग्री ग्लोबल वार्मिंग होने पर 12 प्रतिशत ग्लेशियर बचेंगे, जबकि चार डिग्री ग्लोबल तापमान बढ़ने पर सिर्फ एक प्रतिशत ग्लेशियर बचेंगे। उत्तरी अमेरिका के राकी पर्वत में लगभग 4,400 ग्लेशियर 1.5 डिग्री ग्लोबल वार्मिंग में बचे रहेंगे। सेंट्रल एशिया, जहां सबसे ज्यादा ग्लेशियर हैं वहां हर साल 200-300 ग्लेशियर खत्म हो रहे हैं। अनुमान है कि 1.5 डिग्री होने पर यह दर लगभग 500 प्रति वर्ष हो जाएंगे।

Dainik Jagaran Page No-14

ईयू शिखर बैठक कल से, अमेरिका के बदले रुख के साए में यूरोप की परीक्षा

ब्रसेल्स, एपी: साल 2025 के अंत तक यूरोप के सामने एक कड़वी हकीकत साफ हो चुकी है। दशकों तक सबसे भरोसेमंद सहयोगी रहा अमेरिका अब यूरोपीय संघ (ईयू) की एकजुटता, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और यहां तक कि लोकतांत्रिक मूल्यों को भी चुनौती देता नजर आ रहा है। इसी बदले वैश्विक परिदृश्य के बीच इस सप्ताह ईयू की अहम शिखर बैठक होने जा रही है, जो एक असाधारण रूप से कठिन वर्ष का समापन करेगी।

पिछले सप्ताह यूरोप में रूसी संपत्तियों को अनिश्चितकाल के लिए फ्रीज करने के बाद, अब गुरुवार को होने वाली इस बैठक में ईयू नेताओं के सामने एक और कड़ा इम्तिहान है। यूक्रेन गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है और यूरोपीय नेताओं ने अगले दो वर्षों तक कीव की आर्थिक और सैन्य जरूरतें पूरी करने का वादा किया है। इसके लिए नए पुनर्भुगतान ऋण (रेपरेशंस लोन) की संभावना पर चर्चा हो रही है।

- **अविश्वसनीय सहयोगी के दौर में ईयू के सामने बड़ी चुनौती, सुरक्षा और यूक्रेन पर आत्मनिर्भरता की तलाश**
- **अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में यूरोप पर तीखा प्रहार, सहयोग की बजाय हाथ खींचने के प्रयास में ट्रंप**

बेल्जियम के ब्रसेल्स में हेडक्वार्टर के बाहर फहराते यूरोपियन यूनियन के झंडे। रायटर

यूरोप के सामने खुद को साबित करने की चुनौती

डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोके रासमुसेन ने इसे यूरोप और यूक्रेन के लिए निर्णायक समय बताया। उन्होंने कहा कि यह फैसला न सिर्फ यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को सुरक्षित करेगा, बल्कि वाशिंगटन के व्हाइट हाउस समेत पूरी दुनिया को यह संकेत देगा कि यूरोप एक मजबूत भू-राजनीतिक दावेदार है। महाद्वीप में दशकों के सबसे बड़े जमीनी युद्ध के बीच यूरोप को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों, यूरोप के दक्षिणपंथी दलों के प्रति उनके समर्थन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उनकी नजदीकियों ने लगातार परखा है। शुरुआती दौर में यूरोपीय नेताओं ने नरम रुख अपनाया, लेकिन हाल के महीनों में यह रणनीति कमजोर पड़ती दिखी है।

हम एक निर्णायक मोड़ पर खड़े हैं। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। यह नया समय है और इसके लिए नई तैयारी चाहिए।

- जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने हाल में कहा था

ट्रंप के लिए रूस बनाम यूरोप की रस्साकसी

जनवरी से अब तक ट्रंप का रुख यूक्रेन और रूस के बीच झूलता रहा- कभी कीव के समर्थन में, तो कभी मास्को के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए। यूरोप पर उनकी आलोचना लगातार तीखी होती गई है। हालांकि यूरोपीय नेता मानते हैं कि अमेरिका अब भी अपूरणीय साझेदार है और पुतिन से शांति वार्ता के लिए ट्रंप ही शायद एकमात्र पश्चिमी नेता हों। ट्रंप के सत्ता में लौटने के कुछ ही हफ्तों बाद उनके प्रशासन ने संकेत दे दिया था कि अमेरिकी सुरक्षा हित अब कहीं और हैं और यूरोप को अपनी तथा यूक्रेन की सुरक्षा खुद संभालनी होगी। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बयानों और अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में यूरोप की आलोचना ने इस दूरी को और गहरा किया।

यूरोप पर रक्षा खर्च बढ़ाने का भी दबाव व्यापार व रक्षा के मोर्चे पर भी असर

साफ है। अमेरिकी टैरिफ और युद्ध समाप्ति की विवादित योजनाओं के बीच ईयू ने एशिया समेत अन्य साझेदारों की ओर रुख किया है। साथ ही नाटो में रक्षा खर्च बढ़ाने पर सहमति बनी है और ईयू ने 2030 तक आत्मरक्षा में सक्षम बनने का लक्ष्य रखा है। यूरोप ने 2035 तक रक्षा खर्च जीडीपी का पांच प्रतिशत करने का वादा किया है। वर्तमान में यह दो प्रतिशत भी रक्षा पर खर्च नहीं कर रहा है। अधिकारियों को आशंका है कि यूक्रेन को हराने के बाद पुतिन यूरोप पर हमला बोल सकते हैं।

यूरोपीय देश हथियार खरीदने पर बेहिसाब बहा रहे पैसे। फाइल

Dainik Jagaran Page No-11

पेरिस जलवायु समझौते का एक दशक

सुधीर कुमार

गत 12 दिसंबर को पेरिस जलवायु समझौते के 10 वर्ष पूरे हुए हो गए। जलवायु परिवर्तन पर दो ध्रुवों पर बंटे विश्व को एक मंच पर लाने का एक बड़ा प्रयास 2015 के पेरिस जलवायु सम्मेलन में किया गया था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उस वक्त कहा था कि 'पेरिस समझौते में न कोई विजेता है और न ही किसी की हार हुई है, पर्यावरण को लेकर न्याय की जीत हुई है और हम सब एक हरे भरे भविष्य पर काम कर रहे हैं।'

दरअसल जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में पेरिस समझौते का विशिष्ट महत्व रहा है। इसमें वैश्विक तापमान को दो डिग्री सेल्सियस से कम पर लाने, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को उस स्तर पर लाने, जिसे पेड़, मृदा और समुद्र प्राकृतिक ढंग से अवशोषित कर सकें, 'अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन' का गठन कर नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने, समृद्ध देशों द्वारा गरीब देशों को जलवायु चुनौती से निपटने के लिए संसाधन प्रदान करने जैसे महत्वपूर्ण लक्ष्य शामिल रहे थे।

जलवायु परिवर्तन पर दो ध्रुवों पर बंटे विश्व को एक मंच पर लाने का प्रयास 2015 के पेरिस जलवायु सम्मेलन में किया गया था

हालांकि एक दशक बाद इन उद्देश्यों की समीक्षा करने पर ज्ञात होता है कि दुनिया जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने में लक्ष्य से थोड़ी पीछे रह गई है। इसकी पुष्टि करने वाले प्रमुख तथ्यों में एक है, 2024 का इस सदी के सबसे गर्म वर्ष के रूप में दर्ज होना। यह ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते प्रकोप को अभिव्यक्त करता है। दूसरी तरफ, जलवायु परिवर्तन के एक बड़े कारक के रूप में कुख्यात ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी आने के बजाय बढ़ोतरी हो रही है। वायुमंडल में कार्बन डाईआक्साइड की सांद्रता 2024 के अंत में 422 पार्ट्स प्रति मिलियन तक पहुंच गई। यह सच है कि पेरिस समझौते के तहत अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के अस्तित्व में आने के बाद दुनिया के कई हिस्सों में सौर ऊर्जा सहित अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उत्पादन और उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसके बावजूद यह प्रगति जलवायु संकट की भयावहता के अनुरूप पर्याप्त नहीं कही जा सकती। जीवाश्म ईंधनों पर वैश्विक निर्भरता अब भी बनी हुई है और अनेक विकसित देश, जो ऐतिहासिक रूप से सर्वाधिक उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार रहे हैं, उत्सर्जन में ठोस कटौती तथा जलवायु वित्त के अपने वादों को निभाने में अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखा पा रहे हैं। सबसे अधिक चिंता का विषय यह है कि जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों का सबसे बड़ा बोझ उन विकासशील और गरीब देशों पर पड़ रहा है, जिनका वैश्विक उत्सर्जन में योगदान अपेक्षाकृत कम रहा है।

जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ती गर्मी, अनियमित वर्षा, सूखा, बाढ़ और चरम मौसमी घटनाओं में वृद्धि से आर्थिक और सामाजिक समस्याएं गहराती जा रही हैं। जलवायु संकट के विनाशकारी प्रभावों से मानवता को बचाने के लिए आवश्यक है कि इस दिशा में दुनिया सजगता दिखाए।

(लेखक बीएचयू में शोधार्थी हैं)

Dainik Jagaran Page No-8

इतिहासबोध की दिशा में सार्थक पहल

प्रणय कुमार

एनसीईआरटी का संशोधन वैचारिक अन्याय का उत्तर है। यह इतिहास को न कटुता से लिखता है, न प्रतिशोध भावना से

एनसीईआरटी द्वारा कक्षा सात की सामाजिक अध्ययन की नई पुस्तक 'एक्सप्लोरिंग सोसाइटीजः इंडिया एंड बियांड-पार्ट 2' में किया गया संशोधन केवल पाठ्यक्रम परिवर्तन नहीं है। यह उस वैचारिक जड़ता को तोड़ने की कोशिश है, जिसने दशकों तक भारतीय इतिहास को आधा-अधूरा, चयनात्मक और भ्रमित रूप में विद्यार्थियों के सामने रखा। यह पहल इतिहासबोध की पुनर्स्थापना की दिशा में एक साहसिक और आवश्यक कदम है। स्वतंत्रता के बाद भारतीय इतिहास-लेखन पर एक खास वैचारिक प्रभुत्व हावी रहा। इसके अंतर्गत मध्यकालीन भारत के आक्रमणों को या तो संक्षेप में प्रस्तुत किया गया या उन्हें केवल साम्राज्य-विस्तार और आर्थिक लूट के सीमित दायरे में देखा गया। मंदिर-विध्वंस, धार्मिक उत्पीड़न, गैर-मुसलमानों के व्यापक नरसंहार, दास-व्यापार और ज्ञान-केंद्रों के सुनियोजित विनाश जैसे तथ्य या तो दबा दिए गए या 'सुल्तानों-राजाओं के युद्ध' बताकर खारिज कर दिए गए। इससे भी आगे बढ़कर इन आक्रमणों के पीछे सक्रिय उस वैचारिक मानसिकता पर लगभग मौन साध लिया गया, जो 'कुफ्र-काफिर' की अवधारणा में विश्वास करती है। नतीजा यह हुआ कि इतिहास का एक निर्णायक और पीड़ादायक पक्ष पीढ़ियों तक छात्रों की समझ से बाहर ही रहा।

एनसीईआरटी की नई पुस्तक इतिहास को किसी वैचारिक सुविधा के अनुसार नहीं, बल्कि प्रमाणिक स्रोतों और ठोस ऐतिहासिक संदर्भों के आधार पर प्रस्तुत करती है। सच को सच कहना सांप्रदायिकता नहीं, बल्कि बौद्धिक ईमानदारी का परिचायक है। इस पुस्तक की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि यह भारतीय इतिहास को दिल्ली और उत्तर भारत-केंद्रित दृष्टिकोण की सीमाओं से मुक्त करती है। इसमें काकतीय, चालुक्य, पल्लव, होयसल, पूर्वी गंग, ब्रह्मपाल जैसे वंशों के साथ-साथ भंजा, गुहिल, कलचुरी, मैत्रक, मौखरी, शिलाहार, सोमवंशी, तोमर और चैहमान (चौहान) जैसे अनेक राजवंशों के योगदान को भी समुचित स्थान दिया गया है। इस पुस्तक में मंदिर स्थापत्य को केवल पूजा-स्थल या धार्मिक प्रतीक भर मानकर नहीं देखा गया है, बल्कि उसे मध्यकालीन भारतीय समाज की शिक्षा, कला, विज्ञान और सामुदायिक जीवन के जीवंत केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

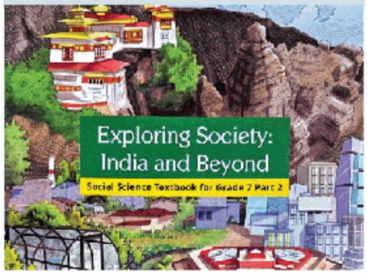

वास्तविकता से परिचय कराती पाठ्य सामग्री। फाइल

बेलूर-हलेबिडु के होयसल मंदिरों की अद्वितीय सूक्ष्म नक्काशी हो या फिर एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर, ये सभी उस तकनीकी दक्षता, स्थापत्य-ज्ञान और सौंदर्य-बोध के ठोस प्रमाण हैं, जिस पर भारत की सभ्यता सदियों तक खड़ी रही। यह प्रस्तुति उस लंबे समय से प्रचारित मिथक को स्वतः ध्वस्त करती है कि मध्यकालीन भारत बौद्धिक, वैज्ञानिक या रचनात्मक रूप से किसी प्रकार पिछड़ा हुआ था। पुस्तक में सम्मिलित 'वसुधैव कुटुंबकम्' और 'इंडिया, ए होम टू मेनी' जैसे अध्याय भारत के उस सभ्यतागत आत्मा को सामने लाते हैं, जिसकी जड़ें सहिष्णुता, सह-अस्तित्व और सम्मान में रची-बसी हैं। यहूदी और पारसी समुदायों को न केवल शरण देना, बल्कि उन्हें सम्मान, सुरक्षा और सामाजिक स्वीकार्यता प्रदान करना भारतीय समाज की ऐतिहासिक परंपरा रही है।

नई पुस्तक में जोड़ा गया 'इंडिया एंड हर नेबर्स' अध्याय में पाकिस्तान के संदर्भ में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उसका निर्माण धार्मिक आधार पर हुआ और विभाजन ने चुनौतियां कम नहीं कीं, अपितु भारतीय मानस को गहरे घाव दिए। यह प्रस्तुति उस वैचारिक भ्रम को तोड़ती है, जिसके अनुसार भारत-पाक विभाजन एक राजनीतिक दुर्घटना मात्र थी। पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंधों को साझा सभ्यतागत विरासत के संदर्भ में समझाने का प्रयास छात्रों को व्यापक दृष्टि प्रदान करता है।

वामपंथी खेमा सर्वाधिक असहज उन अध्यायों को लेकर है, जिनमें महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी और बख्तियार खिलजी के आक्रमणों का विस्तृत वर्णन किया गया है। कारण स्पष्ट है, क्योंकि पहली बार विद्यालयी पाठ्यक्रम में इन आक्रमणों को उनकी वास्तविक वैचारिक पृष्ठभूमि के साथ प्रस्तुत किया गया है। गजनवी के 17 आक्रमण-सोमनाथ मंदिर का विध्वंस, मथुरा और कन्नौज के देवालयों का नाश, बड़े पैमाने पर नरसंहार और स्त्री-बच्चों को दास बनाकर गजनी ले जाना, ये सब अब 'कथा' नहीं, बल्कि ऐतिहासिक तथ्य के रूप में सामने हैं। अल-उत्बी, अल-बिरूनी, फिरदौसी जैसे समकालीन फारसी स्रोत स्वयं स्वीकार करते हैं कि गजनवी अपने अभियानों को 'काफिरों के विरुद्ध जिहाद' मानता था। इसी क्रम में मुहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर किया गया आक्रमण हो, बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा और विक्रमशिला का विध्वंस हो या तैमूर द्वारा 1398 में दिल्ली में किया गया भीषण नरसंहार, इन सभी घटनाओं के पीछे केवल राजनीतिक कारण नहीं थे। स्वयं तैमूर ने 'तुजुक-ए-तैमूरी' में स्वीकार किया है कि उसका अभियान 'कुफ्र के उन्मूलन' की मजहबी प्रेरणा से संचालित था। एनसीईआरटी का संशोधन वैचारिक अन्याय का उत्तर है। यह इतिहास को न कटुता से लिखता है, न प्रतिशोध की भावना से। यह केवल यह कहता है कि इतिहास को जैसा था, वैसा स्वीकार किया जाए। बिना सत्य के न तो आत्मविश्वास संभव है, न सामाजिक समरसता। इतिहास का उद्देश्य समाज को बांटना नहीं, बल्कि उसे उसकी वास्तविक यात्रा से परिचित कराना है।

(लेखक शिक्षाविद हैं)
response@jagran.com

Dainik Jagaran Page No-8

राष्ट्रीय सुरक्षा को चाहिए नई दृष्टि

जगतबीर सिंह

जो पहलू आज राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष चुनौती उत्पन्न कर रहे हैं, वे ओझल नहीं होने वाले। उलटे नई चुनौतियां दस्तक देती रहेंगी

अवधेश राजपूत

भारतीय उपमहाद्वीप के मानचित्र को नए सिरे से बदलने वाली 16 दिसंबर की तिथि को भारत में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। पाकिस्तान के विभाजन और बांग्लादेश के सृजन के रूप में भारतीय सैन्य बलों की यह एक अद्वितीय विजय थी। महज एक पखवाड़े के भीतर भारतीय सेना ने पाकिस्तान को पूरी तरह पस्त कर दिया और उसके 93,000 सैनिकों ने शर्मनाक आत्मसमर्पण किया। हमारे सशस्त्र बलों की पेशेवर कार्यशैली, देशभक्ति, समर्पण, दृढ़ता, संकल्प और साहस ने इस विजय को विशेष बनाया। इस विजय में और भी कई निर्णायक पहलू थे। जैसे सभी स्तरों पर नेतृत्व, राजनीतिक-सैन्य समन्वय, कूटनीति, खुफिया जानकारी, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विशेष रूप से सीमा सुरक्षा बल, रेलवे और मुक्ति वाहिनी की भूमिका भी उतनी ही अहम रही। पूर्व सेनाप्रमुख जनरल वीएन शर्मा के अनुसार 1971 की विजय का सबसे बड़ा मर्म यही रहा कि युद्ध एक सैन्य मोर्चा ही नहीं, बल्कि समग्रता का संघर्ष है, जिसमें राजनीति,कूटनीति भी शामिल होती है। उनकी दृष्टि में युद्ध एक सैन्य कार्रवाई ही न होकर विभिन्न सरकारी एजेंसियों और विभागों का समन्वित प्रयास होता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा एक व्यापक विषय है। परिभाषा की बात की जाए तो कोई भी खतरा जो परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देता है, उसे राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता के रूप में देखा जाता है। हालांकि अब इसे केवल पारंपरिक सैन्य युद्ध के संदर्भ में ही सीमित नहीं किया जा सकता। वर्तमान परिदृश्य आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक-राजनीतिक सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, मानव विकास सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा के साथ कुछ और पहलुओं को जोड़ता है। वर्तमान में पारंपरिक क्षेत्रीय खतरों और हार्ड पावर के साथ ही साफ्ट पावर, जलवायु परिवर्तन, रैनसमवेयर, महत्वपूर्ण खनिजों से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट मीडिया तक सब कुछ राष्ट्रीय सुरक्षा के रूप में वर्गीकृत किए जा सकते हैं। ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, परमाणु प्रसार, मादक पदार्थों की तस्करी, आतंकवाद, साइबर हमले, विदेश में नागरिकों की सुरक्षा और बाजारों की सुरक्षा जैसे कई अन्य मुद्दे भी इस मोर्चे पर उभरे हैं। कोविड जैसी महामारी को भी सुरक्षा के साथ जोड़कर देखा जा सकता है। इस सच्चाई को अनदेखा नहीं किया जा सकता कि आर्थिक वैश्वीकरण और तेजी से आकार ले रहे तकनीकी परिवर्तन ने असामान्य खतरों की संख्या बढ़ा दी है। इसके बावजूद, पारंपरिक खतरों को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता।

समय के साथ भौगोलिक परिदृश्य भी तेजी से बदल रहा है। इसमें अंतरराष्ट्रीय प्रणाली को प्रतिस्पर्धी शक्ति केंद्रों, तकनीकी व्यवधानों और बदल रहे गठबंधनों द्वारा नए सिरे से निर्धारित किया जा रहा है। साइबर, अंतरिक्ष और सूचना युद्ध के रूप में प्रतिस्पर्धा शांति और संघर्ष की रेखाओं को धुंधला कर रही है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मूल्यांकन केवल राजनीतिक और सैन्य ढांचों से नहीं किया जा सकता। इसके मूल्यांकन में समग्र राष्ट्रीय दृष्टिकोण बहुत उपयोगी होगा। यह संकल्पना यही मांग करती है कि सैन्य और नागरिक सरकारी विभागों के बीच आदर्श समन्वय एवं सहयोग सुनिश्चित हो, ताकि एकीकृत प्रक्रिया के माध्यम से साझा सामरिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। यदि भारत को आज की चुनौतियों का समग्र रूप से सामना करना है तो ऐसा समग्र दृष्टिकोण आवश्यक है।

एक विशाल लोकतंत्र और तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था के रूप में भारत राष्ट्रीय सुरक्षा के नए तानेबाने की तलाश के लिहाज से एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। इस बीच क्षेत्रीय गतिशीलता, आर्थिक चुनौतियां, तकनीकी प्रगति और नए आकार ले रहे खतरों की जटिलताएं सुरक्षित और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण को विकसित करने की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं। इसलिए समग्र राष्ट्रीय दृष्टिकोण और भी आवश्यक है। इस कड़ी में अत्याधुनिक हथियारों से सुसज्जित सशक्त सेना का होना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि यह संकल्प अधिक महत्वपूर्ण है कि समय आने पर उनका तत्परता से उपयोग कैसे किया जाए। यह बिंदु भी राष्ट्रीय सुरक्षा के नए ढांचे को परिभाषित करेगा।

समन्वय और सहयोग को प्रोत्साहन देने का सबसे प्रभावी तरीका यही है कि सैन्य और नागरिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों के बीच समय के साथ सुसंगति बनाई जाए। ऐसा न हो कि उन्हें संघर्ष के समय ही एक साथ काम करने के लिए साथ आना पड़े। याद रहे कि भारत को सुरक्षित बनाना एक बहुआयामी प्रयास है। इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों में एकीकृत रणनीति की आवश्यकता है। सामाजिक-राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक समृद्धि, तकनीकी क्षमता, कूटनीतिक कुशलता, मजबूत रक्षा तंत्र और राष्ट्रीय संस्थानों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करके ही भारत 21वीं सदी की जटिलताओं को पार कर एक मजबूत और सुरक्षित राष्ट्र के रूप में उभर सकता है। समग्रता से परिपूर्ण इस दृष्टिकोण को मूर्त रूप देने के लिए नागरिक समाज, अकादमिक एवं निजी क्षेत्र के बीच सहयोग से ही भविष्य की राह खुलेगी। तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत के निरंतर विकास के साथ ही इन प्रमुख घटकों को लेकर प्रतिबद्धता न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, बल्कि देश के सभी नागरिकों के लिए उज्ज्वल भविष्य तथा शांति, समृद्धि का पथ भी प्रशस्त करेगी।

तथ्य यही है कि जो पहलू आज राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष चुनौती उत्पन्न कर रहे हैं, वे ओझल नहीं होने वाले। उलटे नई चुनौतियां दस्तक देती रहेंगी। भारत अपने इतिहास के निर्णायक पड़ाव से गुजर रहा है और वह इस दौर में खुद को कैसे ढालता है, वही उसके दीर्घकालिक लक्ष्यों को निर्धारित करेगा। सामूहिक समाधान तलाशने के लिए समन्वित प्रयास आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य हैं। राष्ट्र के सामने मौजूद अनुमानित और अनपेक्षित खतरों का सामना करने का संभवतः यही इकलौता मार्ग है। इस संदर्भ में 1971 के सबक हमारे लिए मार्गदर्शक होने चाहिए।

(लेखक पूर्व सैन्य अधिकारी हैं)
response@jagran.com

Dainik Jagaran Page No-8